साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार

Webite: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9300755803, 9425125569
Phone Fax: +91 731 2530859

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 5 अंक 15 | प्रति सोमवार इंदौर, 21 नवंबर से 27 नवंबर 2011 | पृष्ठ 8 | मूल्य 2/- रुपए

चीन द्वारा अंदर बाहर से भारत की बर्बादी

लूट से फुर्सत हो तो राष्ट्र की देखें सुरक्षा

शत्रु की ईंट का जबाब पत्थर से देना होगा। सेर को सवा सेर बनना होगा।

हमारा पड़ोसी देश भारत को हर कदम पर मात दे रहा है। उसकी उत्तरी पूर्वी सीमावर्ती देशों में न केवल लगातार घुसपैठ के साथ ही खुले में हमारी सीमाओं में घुस कर लाल रंग से पोतकर अपनी सीमा बढ़ा रहा है। सैनिकों के बंकर नष्ट कर रहा है। अपने हैलीकॉप्टरर्स भारतीय सीमाओं में न केवल उतार रहा है व खुले में हैलीकॉप्टरों के गिरा भी रहा है।

हमारे भ्रष्ट कांग्रेसी डकैतों को राष्ट्र को लूट कर विदेशी बैंक भरने से ही फुर्सत नहीं मिल पा रही है। वो सुरक्षा को लगातार नजर अंदाज कर रहे हैं। भारत में जैसलमेर और पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों में युद्धाभ्यास शुरू किया तो कच्छ से लेकर पंजाब की सीमा तक पाकिस्तान ने लगभग हजारों चीनी सैनिकों के साथ पुनः युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। इससे चीनी सेना

दोहरा खेल खेल रही है। एक तरफ तो वह पाकिस्तानी व भारतीय सेना की रणनीतिकर आंकलन कर रही है।

तो दूसरी तरफ भविष्य में होने वाले युद्ध का हिमालयीन बर्फीले मौसम से लेकर पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तान के क्षेत्रों मे गर्म मौसम में युद्धाभ्यास में अपने चीनी सैनिकों को भी पारंगत कर रही है। ताकि भारतीय सेना को हरहाल मे मात दी जा सके।

कुलजमा में जो निष्कर्ष सामने आया है। वह यह है कि चीनी सेना ने भारत के तीन तरफ थल पर अपनी भविष्य की युद्धाभ्यास की पाकिस्तान ते साथ जो रणनीति तैयार कर रखी है। उससे कच्छ गुजरात से लेकर पंजाब सियाचीन पाक अधिकृत काश्मीर तक वह भारत के विरूद्ध पाकिस्तानी सेना के साथ ही कुछ करेगी जबकि सियाचीन आक्साईचीन से लेकर म्यांमार तक वह भारत के साथ सीधे स्वंय युद्ध करेगा, बीजिंग से लेकर बारहमासी सड़कों पर निर्माण वह वर्षो पहले ही कर चुका है। अब वह तिब्बत से लेकर पाकिस्तान तक रेल्वे लाईन डाल रहा है। (शेष पेज 2 पर)

पूंजीवाद के विरूद्ध अमेरिका व सौ से भी ज्यादा देशों में प्रदर्शन

भारतीय सत्ताधीश धूर्तो लौट आओ मिश्रित अर्थव्यवस्था पर

सत्ताधीशों को मोटे कमीशन के चलते देश को धकेल रहे पूंजिवाद में

विश्व की महान शक्ति समझने वाली देश के गुंडे और अपनी दादागीरी और हथियार बेंचने के लिये मशहूर और दुनियाभर में आतंक को पोषित करने वाले अमेरिका की अर्थ व्यवस्था ध्वस्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है। अमेरिकी बैंको के डूबने का क्रम को 2008 से ही शुरू हो गया था। वैसे उनमें भारतीय अधिकारियों मंत्रियों मुख्यमंत्रीयों नेताओं पूंजीपतियों का भी करीब रुपये 25 लाख करोड़ से ज्यादा डूब गया। जबकि भारतियों का सारा पैसा कालाधन था। और इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को आसानी से पटरीपर लाया जा सकता था। बशर्ते कि उन सारी बैंको का राष्ट्रीयकरण समय रहते कर दिया जाता। 200 से ज्यादा बैंको के डूबने के साथ ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था के डूबने के शुरूआत के संकेत स्पष्ट थे। इसके विपरीत भारत के सत्ताधीशों ने तीन वर्ष बाद भी सबक नहीं सीखा और ये धूर्त डकैतों की फौज नेहरू गांधी की बनियादी मिश्रित अर्थव्यवस्था को समाप्त कर सभी सेवाएं संचार यातायात विद्युत वृहद धातु उद्योग

अमेरिका और युरोप के पूंजीपतियों का फैलाया विश्व व्यापार संगठन का महाजाल गरीब अविकसित अर्द्धविकसित और विकासशील राष्ट्रों की जनता के शोषण का ही शिगूफा था। तकि ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां इनकी आड़ में वहां के प्रकृतिक संसाधनों और जनता का शोषण कर अपना स्तर हीन समयवाधित चलन से बाहर माल को खपा कर अपना धन कई गुना ज्यादा वसूलेंगे इसके साथ वहां संचार चिकित्सा विद्युत सड़कें रेल जल ईंधन वायु आदि की हजारों गुना ज्यादा कीमत वसूली जाएगी। जिसका वर्तमान दौर भारत में चल रहा है। वॉल स्ट्रीट जो विश्व का जाना माना शेयर बाजार है जनता की अंश पूंजी के दम पर जनता का ही शोषण करने वाली कंपनियों के विरुद्ध बढ़ती बेरोजगारी आंतरिक बाहरी राष्ट्रीय कर्ज कर्मजोर होती और गिरती अमेरिकी अर्थ व्यवस्था जो विश्व के सौंकड़ों राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था बिगाड़ने पर तुली हुई थी। स्वयं पटरी से उतर कर अपने अस्तित्व को बचाने में लगी है। अमेरिका के 400 पूंजीपतियों जिनके पास अंशपूजी के रूप में व्यापार व्यवसाय हेतु जनता का ही पैसा था जो जनता का ही शोषण कर जनता बेरोजगारी भुखमरी की कगार पर ला खड़ा किया है। जो आग अमेरिका के इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के खिलाफ भड़की है। वही इंगलैंड और लगभग सौ यूरोपिय माल तो भी राष्ट्रों में भड़क चुकी है।

(शेष पेज 2 पर)

सत्ताधीश धूर्तो, देश बाप की जागीर नहीं

सूचना का अधिकार वयस्कता से पूर्व ही हत्या पर उतारू

गिद्धों नोंचो और विदेश भेजों जनता को महंगाई से रोटी भी न मिले

भारत में सत्तासंभाल रही डकैतों और गिद्धों की फौज का पिछले शासन में एक कार्य ही अच्छा किया था कि 58 वर्ष की आजादी के बाद सूचना का अधिकार आधिनियम 05 लागू किया था जो पिछले कांग्रेस की एक मात्र श्रेष्ठ उपलब्धी थी जिस पर वह बेमन से नाज करती है। सूचना अधिकारी अधिनियम 05 को लागू हुए 6 वर्ष अवश्य बीत गए पर अभी भी शासकीय निकम्मेपन जालसाजियों व बत्तमीजियों का घोर शिकार रहा है। 6 वर्ष बाद भी इसका ढंग से पालन नहीं हो पा रहा है। यह हाल केन्द्र के सभी विभागों जिसमें राष्ट्रीय सूचना केन्द्र राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों मुख्य सचिवों तक की साईडों तक पर धारा 4 की समस्त जानकारी 6 वर्ष तक नहीं डाली गई है।न ही सरकारी हरामखोर गिद्ध डकैतों की अपनी सच्चाईयों को डालने की योजना है। क्यों कि डालने से इन शूकरों की फौज की वास्तविकता जनता और पत्रकारों तक

पहुंचाने का खतरा है। बहाना केन्द्र राज्य सरकारों के सभी विभागों के अधिकारियों का पास एक ही है कि नियमित कार्यो को पूरा करें या साइटों पर सारे रिकार्ड और दस्तावेजों को अपलोड करें जबकि इन मक्कार श्वानों की सत्यता यह है अब अधिकांश केन्द्र राज्य सरकारों के अधिकांश विभागों के 70 से 80 प्रतीशत कार्य कंप्यूटर्स से होने लगे हैं। अधिकांश भुगतानों ई भुगतान की व्यवस्था कर ली गई है। तो फिर क्यों ये सरकारी भेड़ियों की फौज धारा 4(1) अ और ब के 17 बिन्दुओं की जनकारी साइटों पर डालना नहीं चाहती इसीलिये ही कि जनता से लूटे गए धन का हिसाब जनता को क्यों बताया जाये? क्यों कि सरकारी चपरासियों और बाबुओं से लेकर मुख्यसचिव मुख्यमंत्री राष्ट्र के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कार्यालय तक के दम पर भ्रष्टाचार का अंबर लगा है। लाखों करोड़ो रुपये हर वर्ष हजम कर लिये जाते हैं। और जनता को कभी खबर नहीं होने दी जाती है। जबकि धारा चार के 17 बिन्दुओं का पालन का सबसे बड़ा लाभ शासन को ही मिलना था, कम से कम रोज हजारों पत्र लाखों रुपये से लेकर अरबों रुपये व हजारों घंटे मानव श्रम की बर्बादी से बचा जा सकता था। इन सूचनाओं को एक दूसरे विभाग में भेजना समीक्षा करना आदि का बोझ आसानी से समाप्त ही किया जा सकता है (शेष पेज 3 पर)

म.प्र.की प्रशासनिक व्यवस्था ध्वस्त होने की कगार पर

परीक्षाओं से हो शीघ्र भर्तियां और पदोन्नतियां

कार्यशील स्टॉफ 12,13,14 में से सेवानिवृत्ति के कगार पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी पदोन्नतियों में आरक्षण क्यों?

पूरे मप्र में सभी 100 से ज्यादा विभागों में छोटे अधिकारियों और कर्मचारियों के भर्तियां पिछले बीस वर्षो से ज्यादा समय से विश्व व्यापार संगठन और स्टाफ घटाओ खर्च मिटाओ के अंतर्गत बंद कर रखी है। जिसे वर्तमान में भारी स्टाफ का संकट भोपाल के मुख्यालयों से लेकर संभागों जिलाकार्यालयों तहसील और विकास खंड स्तर तक छाया हुआ है। पिछले बीस वर्षो से अधिकारी कर्मचारी हर वर्ष सेवा निवृत्त किये जा रहे हैं। पर नये स्टाफ की भर्तियां न होने से जनसंख्या कारणों के प्रकार विभिन्न कार्यो में न केवल कार्यालयो में वरन मैदानी स्टाफ की हर विभाग में भारी कमी से जूझना पड़ रहा है। पुलिस विभाग को ही ले लें तो मुख्यालय भोपाल से लेकर थाने तक में सिपाहियों हेड कॉस्टोबलों उप निरीक्षकों निरीक्षकों तक का तीन शिफ्टों में काम करने वाला स्टाफ चाहिये। इस दृष्टिकोंण से अकेले पुलिस विभाग में ही लगभग एक लाख कांस्टेबल से 2हजार सहायक निरीक्षक एक हजार निरीक्षक और तीन सौ निरीक्षकों की तत्काल आवश्कता है। ताकि अपराधों पर लगाम लगाने के साथ ही वर्षो से लंबित बड़े मुकदमों में शीघ्र जांच और कार्रवाई की जाए प्रदेश की जनता 6.50 करोड़ हो चुकी है। अपराधों का तरीका आत्याधुनिक और 24 घंटे चलने वाला हो गया है। सिपाहियों से निरिक्षकों तक को न तो छुट्टियां 12से 14 घंटे काम आखिर कब तक जोतेंगे जानवरों की तरह आखिर ये भी इंसान हैं। छुट्टी के नाम पर हत्याएं आत्महत्याएं रोकने वाले 12 से 14 घंटे काम करने के बाद स्वमं अपराधी बन जाए तो फिर नया क्या होगा।

यही हाल शिक्षा विभाग में लोकनिर्माण विभाग लोकस्वास्थ्य यांत्रिकीय जल संसाधन ग्रामीय यात्रिकीय आदि में उप यंत्री से लेकर सहायक कार्यपालन यंत्रियों तक की भारी कमी का आलम है। हर विभाग में आवश्यकता के विपरीत 35 प्रतीशत स्टाफ से काम चलाना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग में न सिर्फ डॉक्टरों वरन रेडियोलाजिस्ट पेरामेडिकल स्टाफ सर्विसेज स्टाफ नर्सेज से लेकर वार्ड बॉय से सफाई कर्मी तक की कमी है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन में भी 50 जिलों में भी कुल मिलाकर मात्र 50-55 औषधि नियंत्रक है। जब कि हर जिले में कम से कम 3 से लेकर 10 औशधि निरीक्षक होने चाहिये अर्थात 300 निरीक्षक चाहिये। इधर भोपाल में ही 10-10 निरिक्षक चाहिये वाणिज्य कर विभाग में भी कम से कम हर वृत्त में 5 बाबुओं की आवश्यकता है। कम से कम तीन कंप्यूटर आपरेटर इसके साथ कर निरीक्षकों जो हर वृत्त में 5 होना चाहिये।

(शेष पेज 3 पर)

साप्ताहिक समय माया

संपादकीय

सभी प्राणी पृथ्वी के यात्री

बाप की जागीर नहीं सत्ता

पृथ्वी पर मानव सभ्यताओं का इतिहास करोड़ों वर्ष पुराना है इस धरा पर जीवों की करोड़ों प्रजातियों में मानव नाम का जीव ही सबसे बड़ा बुद्धिमान होने के साथ ही सबसे बड़ा घोर लालची स्वार्थी और मूर्ख भी है।

प्रकृति ने सभी व्यक्तियों मे बुद्धि सोच और जीवन जाने की कला प्रकृतिक रूप से दी है मानव को उसने जितना बुद्धिमान और चैतन्य बनाया उतना ही मूर्ख और जड़ भी बनाया।

मानव मे ही उसने घोर लालची औव स्वार्थी प्रवृत्तियां भर कर मूर्खता पूर्ण कृत्यों का सतत प्रवाह मृत्यु के अंतिम क्षणों तक प्रवाहमान रखा। मानव सभ्यताओं के विकास के साथ इस बुद्धिमान प्राणी ने अपने ही बीच से या उनके बीच से बड़े बुद्धिमान ने अपनी समाज के अन्य मानवों का नेतृत्व करने उन्हें जीवन की सुखद राह पर चलने का बीड़ा उठाकर सत्ता संभाल ली वह राजा, प्रशासक, मंत्री, प्रधान, मुखिया,पटेल चौधरी बन चलाने लगा। उसकी प्रजा या जनता ने उसे अपना मुखिया मान उसके अनुसार चलने उसका अनुसारण करने ताकि वह भविष्य सुख व समृद्ध बनाने हेतु कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। पर उस मुखिया प्रधानमंत्री ने उसे मूर्ख मान शोषण करना शुरू कर दिया। उसे जनता निहायत जानवर लगने लगी। और उसे अपने स्वार्थ के लिये हांककर निचोड़ने मात्र में विश्वास करने लगा।

हमारे राष्ट्र के संबंध में राष्ट्रीय मुखिया उसके सहयोगी मंत्री अधिकारि भी जनता को जानवर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं समझते। पृथ्वी पर प्रकृति का नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। जिस शरीर के साथ उसने जन्म लिया था जीवन यात्रा पूरी होने के साथ ही उसे शरीर भी त्यागना पड़ता है। पृथ्वी पर यह सब मानव सभ्यता में उसके प्रादुर्भाव से वर्तमान तक उसकी सभ्य समाज को सुचारू रूप से चलाने हेतु जन्मे सभी धर्मो का सार तत्व रहा है।

इसके विपरीत वर्तमान मे आत्याधुनिक होने का दंभ पालने वाली आम जनता से लेकर सत्ताधीश तक सब अपने ही संरक्षितों का घोर शोषण कर अपने लिये धन जमीन जायदाद इकट्ठी करते हैं। देश की सीमाओं में वह धन एकत्रित नहीं कर पाता तो विदेशों में संरक्षित करता है। वह अपने इन कृत्यों को अपनी बुद्धिमानी का हिस्सा मान कर बड़ा खुश और गौरवांन्वित महसूस करता है। जबकि उसके चीरनिद्रा में लीन होते ही उसके अपने ही चंद मिनटों में सुपुर्द ए खाक कर देते हैं। इसके विपरीत वर्तमान भारत में सत्ताधीश जिन्हें जिन्हें जनता ने अपने सुखद भविष्य की कामना से सत्ता सौंपी थी ये सत्ता संभालते ही उसी जनता के जीवित जानवरों की गिद्ध चील कौओं जो मृत जनवरों को नोंचते हैं से भी ज्यादा निम्नता से नोंच कानून और सत्ता के भय के नाम पर नोंचने में लगे हैं।

सत्ताधीश सत्ता को अपने बाप की जागीर समझ नोंच रहे हैं। जनता रूपी जानवर में सींगो के उपयोग की तो दूर अपनी पूंछ भी नहीं हिला सकती ताकि ये सत्ताधीश रुपी चील, कौअे, गिद्द, उसे नोंच न सकें, जिस सड़क बिजली पानी के दम पर भाजपा सत्ता में आई थी वर्तमान में अधिकांश मप के राजमार्गो को रोड डकैत कार्यो के माध्यम बीओटी ठेकेदारों को सौंपने के बाद 60 प्रतीशत सड़कों पर अब वसूली भी होती है। फिर भी गड्ढे और खराब सड़कों का समाना करना ही पड़ता है जनता को, इन शूकरों की फौज सड़कों के ठेकेदारों से महीना वसूल कर अपनी जिम्मेदारी से बच लेती है जिसके सीधे उदाहरण है रायसेन राजगढ़ मार्ग उज्जैन झालावाड़ मार्ग व अन्य कई।

स्वर्णिम मध्यप्रदेश का सपना दिखाने वाले पूरे म.प्र को कैसे अंधेरे में डुबोने पर तुले हैं। इसका अंदाज इसी बाते से लगया जा सकता है कि उस आजमगड़िया आतंकवादी जिसके आंतक ने लोकनिर्माण विभाग को बंद करने के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। वह गिद्ध प्रधान सचिव सुलेमान ने अक्टूबर के अंतिम सप्ताह 1200 मेगावाट से ज्यादा कोयले से ताप विद्युत बनाने वाले सारणी की अधिकांश इकाइयों को अपने कमीशन डकारने और निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिये बंद कर दिया। इसके चलते अब महानगरों में दिन में भी फीडर लाइन बिजली कटौती की जाने लगी है। जबकि पूर्व से ही गांवो में मांग 4 घंटे स्तरीय नगरों अर्थात तहसीलों और छोटे जिलों में मुश्किल ही 12 घंटे विद्युत प्रवाह सामान्य रहता है। नव. दिस. जनवरी फरवरी मे जब सिंचाई के लिये किसानों को मढ़ाई के लिये बिजली की आवश्यकता होती है। तब हाल और बुरे ही होंगे। कुल मिलाकर मप्र विद्युत मंडल की कंपनियां बनाकर इंडियन एव्यूमिंग सेवा के अधिकारियों ने हर वर्ष रुपये 500 से 1000 करोड़ डकार कर हर कंपनी के चिट्ठे में 1000 से 2000 करोड़ का घाटा दिखाया। वर्ष में 50 से 200 गेज मीटर लगा कर दो बार कीमतें बढ़ाकर भी प्रबंध संचालकों से लेकर सचिव प्रधान सचिव ऊर्जा मंत्री मुख्यमंत्री सचिव और मुख्यमंत्री को बस अरबों रुपये विद्युत खरीदी में कमीशन मिले से मतलब है। दूसरी ओर चलते जल और ताप विद्युत स्टेशनों को पहले बंद करो फिर बेचो वहीं हाल कंपनियों का होगा पहले घाटा दिखाओं अपनों को लूट और वसूली के ठेके दिलवाओ फिर कंपनियों की खरबों की संपत्तियों को अरबों में बड़े पूजिपतियों की भेंट वहां भी अरबों रुपये का कमीशन हजम कर जाओ ये भाजपाई शूकर जिस पूजिवाद की राह चलकर अंबानी बंधुओं और टाटा व अन्य पूजिपतियों के चरणों में लोट लगा रहे हैं। अमेरिका और यूरोप में पूजीवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलनों को देख समझ नहीं पा रहे हैं।जनता के तन मन धन पर लगातार चोट पहुंचा रहे हैं। चारों तरफ अंधेर गर्दी और भ्रष्टाचार और अंधेरा फैलाकर भी मध्यप्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बता रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही कि नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जला जा रहा था। शिव स्वर्णिम मध्यप्रदेश बता रहे हैं। जबकि मध्यप्रदेश की सरकार में बैठे सचिव सरकारी अधिकारी कर्मचारी भारी भ्रष्टाचारी अंधेर गर्दी मचा रहे हैं। और मध्यप्रदेश की जनता अंधेरे में डूबी जा रही है। बिजली पेट्रोल करों की लूट से त्राही त्राही कर रही है। मुख्यमंत्री शिव भ्रष्टगणों की धुन पर नृत्य करते हुए स्वर्णिम मध्यप्रदेश चिल्ला रहे हैं। एक तरफ बेटियों को बचाने का राग अलाप रहे हैं। दूसरी जीवित बेटियों को बचाने का राग अलाप रहे हैं। दूसरी ओर जीवित बेटियों के कुपोषण के जरिये मौत के मुंह मे धकेल रहे हैं। महिला बाल विकास से लेकर मंत्री रंजना बघेल से लेकर प्रधानसचिव, सचिव, संचालक, जिले की महिला बाल विकास अधिकारी से लेकर बाल वाड़ी कार्यकर्ता तक विशुठ दोनों हाथों से कागजी खाना पूर्ती कर गिद्दो की फौज झूठे आंकड़ों का करिश्मा दिखा रही है। वही हाल म.प्र के स्वास्थ्य विभाग का है। जो राज्य का केन्द्र का विश्व स्वास्थय संगठन का लगभग रुपये 5000 करोड़ से ज्यादा जीम जाती है। जनता कहीं दवाओं के आभाव में तो कहीं गिद्ध डाक्टरों के ड्रग ट्रायल में मर जाती है। फिर भी सत्ता स्वर्णिम मध्यप्रदेश चिल्लाती है। यही हाल हर विभाग का है।

लूट से फुर्सत हो तो राष्ट्र की देखें सुरक्षा

पेज 1 का शेष...

दूसरी ओर जो सड़क भारतीय सीमा से गुजरात से लेकर पंजाब तक इतनी चौड़ी बनाई गई है तकि उन पर बड़ी आसानी से लड़ाकू विमानों को उतारा जा सके। और उड़ान भरने योग्य है। जहां तक उसकी नौसेना का सवाल है तो उसने भारत को कलकत्ता से लेकर श्रीलंका तक घेरने के लिए श्रीलंका से हाथ मिला ही लिया है। मुंबई और गुजरात के समुद्र तटीय क्षेत्रों में तो कराची से प्रबंध करेगा।

भारत के आंतरिक क्षेत्रों में तो नक्सलवादी बंगाल उड़ीसा छत्तीसगढ़ तक फैले हैं। उनके पास चीनी बंदूके और गोलाबारूद को माओवादियों जो कि विशुद्ध चीनी सहायता से चल रहे हैं। माध्यम से उन्हें पहुंचाया जाता है। भारत सरकार मानती है कि खतरा दोहरा तो मात्र सीमाओं पर है। परन्तु तिहरा खतरा देख में अंदर से नक्सलियों की ओर से आंतरिक और बड़ा है।

पाक और चीनी सैन्य खतरों के सीमा पर परिणामों को तो चाहे जब समाचार पत्रों में पढ़ा ही जा रहा है। जबकि भारत के व्यवसायित ढांचे को भी चीनी स्तरहीन माल से न केवल समय से लगातार देखा जा रहा है। अब चीनी दियों और मूर्तियों पटाखों से तक प्रमाण देखा जा सकता है। जो भारतीय मजदूरों से लेकर उद्योंगपतियों तक को नष्ट हर रहा है। वह केवल कम्प्यूटर सेलफोन घड़ियों से लेकर बल्बों झालरों स्विचबोर्ड से लेकर वस्त्रों जूते चप्पल दवाईयों के बाजार में वर्षो पहले उपस्थित सन् 90 से लेकर 2000 तक ही दर्ज करवा चुका था। स्वाभाविक है कि भारत के लघु और मध्यमवर्गीय व्यापार को भी बर्बाद कर दिया है। अब तक लोहे सीमेंट भारी मशीनरी एक्सरे वेटर मशीनों तक को भी विदेशों के साथ भारत में न केवल आपूर्ती कर रहा है वरन भारत के भारी मशीनरी उद्योग के साथ लोहे सीमेंट उद्योग को भी बर्बाद कर रहा है।

दूसरी ओव विश्व व्यापार संगठन की आड़ में चीनीयों ने भारत के ही क्षेत्रों में उत्पादन करने भारी उद्योग लगाने बड़ी बड़ी परियोजनाओं के ठेके बहाने देश में घुसकर चप्पा चप्पा जानकारी इकट्ठी कर रहा है। अर्थात चीन से न केवल बाहरी वरन आंतरिक खतरे भी भारी होने के बाद भी न केवल केन्द्र के मंत्री वरन सब कुछ जानने के बाद भी अपने कभी राज खोरी व वसूली के लालच में उन्हें प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित कर आया है। साथ ही शत्रु के घर में उसी की प्रशंसा कर अपने देश व प्रदेश की सत्ता की अपने निकम्मेपन और नाकार प्रवृतियों का स्पष्ट बयान कर आया है। जबकि चीनी तकनीकि और सामान कैसी भी और किसी भी प्रकार की पूर्णतः अविश्वसनीय होती है। जो पूरी दुनिया में कुख्यात है। यही सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु हमें गुणवत्ता औव विश्वनीयता के आधार पर विश्व की सिरमौर बना सकता है। यह आदिकालीन सिद्धांत है कि सत्रु कि हर कमजोरी ही हमारी जीत का आधार होती है। बशर्ते कि हमारे केन्द्र व राज्यों के सत्ताधीश जो कमीशन खोर व डकैत हैं अपनी इस नीच मानसिकता को त्याग कर राष्ट्र से हृदय से समर्पित होकर जनहित व कल्याण की सोचें तो हम न केवल चीन से आंतरिक और बाहरी स्तर पर न केवल सामना करने की तो दूर चीन को न केवल सीमाओं पर वरन अंतराष्ट्रीय स्तर पर खासी पटकथा देकर उसे उसकी औकात दिखा सकेंगे।

शुभ संकेत है कि चीन के विरूद्ध समय माया के पूरे राष्ट्र में एकल लेखन पर कम से केन्द्र सरकार ने संज्ञान लेना प्रारंभ कर दिया है, जिससे चीन के आक्रमक तेवरों से वह रक्षा की मुद्रा में आ गया है, पर ये तत्कालिक है। चीन को न केवल हमें सीमाओं पर वरन अंतराष्ट्रीय मंच पर भी न केवल उसके माल की अविश्वसनीयता बल्कि नीच मानसिकता के व्यापक प्रचार प्रसार की व्यवस्था करने के साथ ही उसके तिब्बत हड़प जाने की घटना की सार्वजनिक निंदा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर करने के साथ ही तिब्बतियों के स्वतंत्र राष्ट्र की नीति का समर्थन करने के साथ ही आर्थिक सामरिक सामाजिक समर्थन न केवल भारत के सत्ताधीशों को करना चाहिए वरन अंर्तराष्ट्रीय मंच उनके समर्थन की मांग और गुहार भी लगानी है ताकि शत्रु को हर कदम नीचा देखने हड़पो नीति की नीच मानसिकता को त्यागना पड़े और पाक जैसे नापाक पड़ोसी शत्रु को भी उसका साथ निभाने के लिए हर कदम सोचना पड़े ताकि वह भारतीय माओवादी नक्सलियों का साथ देने से पहले सोचे

इसका सबसे बढ़िया जवाब होगा कि तिब्बतियों को पाकिस्तानी व चीन के बने हथियारों तथा रिवाल्वरों से लेकर मिशाइल लांचरों और विमान भेदी मिसाइल और राकेट तक से हैं। सक्षम बनाया जाना चाहिये अधिकतम तीन वर्ष में तिब्बतियों को चीन मे ही गुरिल्ला युद्ध के लिये तैयार तिब्बत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करवाकर अमेरिका नार्वे और युरोप की मान्याता दिलवा दी जाने से चीन टूटकर पहले आंतरिक युद्ध को शांत करने में लग जायेगा।

फिर पाकिस्तान तक रेल्वे लाईन बिछाना पाकिस्तान के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास करना सीमाओं पर आगे बढ़कर हड़पना हैलिकॉप्टर गिराना का इस प्रकार जबाब दिया जाना चाहिए। इसके लिए तिब्बती प्रजाती के नाक नक्श वाले लोगों की 10-20 बटालियन को सैन्य प्रशिक्षण और धन भारत को मुहैया करवाना चाहिये। जो अगले 20-25 वर्ष तक की सुरक्षा में काम आयेगा।

भारतीय सत्ताधीश धूर्तो लौट आओ मिश्रित अर्थव्यवस्था पर

पेज 1 का शेष

इसकी खबरें भारत में 10 अक्टूबर 11 से लेकर 3 नव. 11 तक पूंजीपतियों जिसमें अंबानी टाटा विरला आई टी सी हिन्दुस्तान लीवर से लेकर लगभग पांच सौ से ज्यादा बड़ी कंपनियो ने भारत में भी जनता से अंश और ऋण पूंजी के रूप में धन एकत्रित कर जनता का ही घोर शोषण करने में लगी है।

ने मिलकर सभी सत्ताधीशों के साथ सभी दृष्य और मुद्रित प्रसार माध्यमों से भारत में वास्तविकता के प्रदर्शन में प्रतिबंधित कर रखा था। इन पूंजिपतियों उद्योगपतियों के साथ ही केन्द्रीय और राज्यों की सत्ता ने भी जनता के शोषण के विरुद्ध भड़क उठने के डर से भारत में किसी का प्रचार प्रसार नहीं किया जा रहा था। आखिर अंबानी की रिलायंस ने और अन्य कंपनियो टाटा की स्टील लोकोमेटिक्स , दूरसंचार, रसायन, करों व अन्य सैकड़ों कंपनियों में तो अंश पूजी के रूप में करोड़ों लोगों का पैसा लगा है। उस पैसे से इस राष्ट्र के मात्र 25 पूंजी जिसमें अंबानी बंधु टाटा भारती बिरला गोदरेज टीवीएस बजाज जैसे पूंजीपति घराने बहुराष्ट्रीय कंपनियों में आईटीसी हिन्दुस्तान लीवर होंडा जैसे लोगों ने राष्ट्र के लोगों की 60 प्रतीशत पूंजी पर कब्जा कर रखा है। वर्तमान में अंबानी बंधुओं की रिलायंस ने बिजली कपड़ा सेलफोन पेट्रोल से लेकर साग सब्जियों तक के बाजार पर कब्जा कर रखा है। और कदम कदम पर देश की 25 करोड़ आबादी का शोषण कर रहे हैं। और वैध अवैध रुप से लगभग रु. 10000करोड़ प्रति दिन से ज्यादा बटोर रहे हैं। राष्ट्र के कोषालय में आयकर बिक्रीकर कस्टम ड्यूटी के नाम पर भी सरकार में बैठे प्रधान मंत्री के लेकर सबको मुह के आकार का टुकड़ा डालकर हजारों करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। इसलिए वे पूरी सरकार नचा रहे हैं। कानून बनवा रहें है और जनता का खून पिये जा रहे हैं। भारत इंडियन आईडिल और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम से अपना अपना पेट्रोल बिकवा रहे हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ती रहे अब बिजली में आ रहे हैं। सारे देश के मंडलों को खत्म करके कंपनियां चलवा रहे हैं। हजारों करोड़ों रुपये उनके एमडी अध्यक्ष डकारे जा रहे हैं। फिर हजारों करोड़ के घाटे दिखा रहे हैं। धीरे से ये अंबानी बंधु सामने आएंगे। लाखों करोड़ों की संपत्तियों पर ये कब्जा जमाएंगे। फिर विद्युत उत्पाद और वितरण कंपनियां ये चलाएंगे। जनता के अंधेरे में ले जाएंगे फिर बिजली की कीमतें बढ़ाएंगे। इन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रयी और बहुंराष्ट्रीय कंपनियों जिनकी पूंजी रु. 10000 करोड़ रुपये से ज्यादा है सबका राष्ट्रीयकरण करो जनता को रोजगार दो अन्था अमेरिका जैसे आंदोलन के लिए तैयार रहो।

समय माया ने अमेरिकी पूंजीवाद विश्व व्यापार संगठन और संयुक्त शैतान (राष्ट्र) संघ अमेरिकी चालबाजियों के विरूद्ध जो विश्व के विकास अर्धविकास शील अर्द्ध विकसित, अविकसित राष्ट्रों के शोषण और अपने माल व सेवाऐं बेंचने का साधन बन गयी थी। लगातार अब ये शौसल काल से ही लिखा था कि ज्यादा अमेरिका नाटो और युरोप तुम्हारी चालबाजियां ज्याद दिन नहीं चलेगी। कभी भी तुम्हारे गले का फंदा बन जाएंगी। सत्यता सामने है। अमेरिकी पूंजिपतियों अमेरिका की चालबाजियों अमेरिका के साथ यूरोप के 100 देशों में जनता पूंजीवाद के शोषण के विरुद्ध आंदोलन कर रही है। पूंजिवाद की कठपुतली न्यायालय वास्तविकता को समझनें के विपरीत आंदोलन कुचलने पर तुले हैं। ब्रिटेन जिसके साम्राज्य का कभी सूरज नहीं डूबता था। अपने देश में ही सूरत की रोशनी अब अंधकार बनने लगी है।

दुनिया के गरीब देशों को वैश्यावृत्ति का रूस को बर्बाद कर वहां की औरतों, ईराक और अफगानिस्तान की औरतों के कपड़े उतरवाकर वैश्यावृत्ति पर मजबूर करने वालों करवाओ अपनी औरतों से पेट भरने के लिए वैश्यावृत्ति।

इसके विपरीत समय माया की साइट ने सलाह दी है कि जितनी भी बड़ी सेलफौन आदि की बड़ी कंपनियां है। उनका राष्ट्रीय करण करो युवा पीढ़ी को रोजगार दो मिश्रित अर्थव्यस्था अपनाओ।

भारत के धूर्तो जो सत्ता में बैठे हैं। तुरंत प्रभाव से पूंजीवाद को रोककर मिश्रित अर्थव्यवस्था नेहरू गांधी की परंपरा ही चलाना चाहिए। अन्यता जो हाल अमेरिका के हो रहे हैं। वही हाल भारत के होंगे। पूंजीवादी शोषण के विरूद्ध जनता कभी भी उठ खड़ी होगी।

राऊ की फैक्ट्रीयों में बाल श्रमिकों की मौत

श्रम व औ. स्वा. एवं सुरक्षा विभाग केवल महीना वसूली

फटाका फैक्ट्रियों में बाल श्रमिकों की भरमार
अत्याचार शासन के फैसलों की बाजी मारी

इंदौर से मात्र 10 किमी की दूरी और ए.बी रोड पर स्थित राउ गांव में पिछले 30-35 वर्षो से हर तीसरे घर में चल रही फटाका फैक्ट्रीयों में हजारों बाल श्रमिक कार्यरत हैं। जो फटाकों के सबसे लोकप्रिय फटाके रस्सी बंम और अनार की मटकियों में बारूद भरते हैं और रस्सी लपेटते हैं। 6 अक्टूबर को हुये एक फैक्ट्री में विस्फोट से हुई 6 लोगों की मौत 2 ने बाद में अस्पतालों में दम तोड़ा जब प्रशासन नें छापे मारे तो टनों से अवैध फटाके जप्त हुए छापे मारने और पकड़ धखड़ की गति धीमी होने से टनों से फटाके दीपावली के समय चलते उज्जैन, देवास इंदौर से लेकर खंडवा खरगोन धार बड़वानी से लेकर प्रदेश के बाहर भेज दिये गए। जिसमें पुलिस वसूली और संरक्षण के रोल में थी।

इंदौर मे पूरे प्रदेश के श्रम विभाग का मुख्यालय है। साथ ही इंदौर शहर के लिये उपायुक्त सहायक श्रमायुक्त का कार्यालय भी है। जहां 20 से ज्यादा श्रम निरिक्षक विराजते हैं। जो पूरे इस महानगर इंदौर से सिर्फ वसूली करते हैं। हालात यह है कि पोलोग्राउंड के अधिकांश फैक्ट्रीयों से लेकर पाकीजा जैसे बड़े शॉपिंग सेंटर्स पर नही महिला कर्मचारियों को भी 8-10 घंटे कार्य करने के जिलाधीश स्तर के 121.5/- प्रतिदिन की तो दूर मासिक रु 2500 रुपये देते हैं। यही हाल उन बाल श्रमिकों का भी है। जिन्हें 10-12 घंटे काम के मात्र 70 से 80 रुपये ही मिलते हैं। सारे शूकरों की श्रम निरिक्षकों की फौज के बद ऐसे सभी संस्थानों से महीना वसूलकर तान सोते हैं। वही हाल मप्र औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के निरीक्षकों को से लेकर अधिकारियों तक का है। जब ये मामला औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से जुड़ा हुआ था। जहां घातक ज्वलनशील अत्यधिक असुरक्षित विस्फोटकों का उपयोग होता था और किसी भी फैक्ट्री और फटाका निर्माता के यहां 40-50से कम मजदूर नहीं थे। तो विभाग का यह कहना है कि हमारे यहां पंजीकृत नहीं है। और वहां शक्ति का उपयोग नहीं होता था। निहायत मूखर्ता पूर्ण हो न हो पर निहायत जालसाजी पूर्ण जरूर होता था। और यह कहकर इससे जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते थे। इसके विपरीत औ. स्वास्थ्य सुरक्षा के निरिक्षक नियमित रूप से महीना वसूली कानूनों का भय दिखाकर अवश्य करते थे। अर्थात महीना वसूली में तो कानून लगता था। पर दुर्घटना में अपनी गर्दन फंसते देख साफ मुकर गए। भारतीय औद्योगिक अधि. 1948 की परिभाषा में ही नहीं था। इसलिये हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती इस बात को जिलाधीश और संभागायुक्त ने भी आंख मीच कर मान लिया। जो सरासर गैर कानूनी था। साथ ही इस विभाग को कारखानों में काम करने वाले बाल श्रमिकों महिलाओं और उनके बच्चों की सुरक्षा के लिए कानून संम्मत जो धारा 11 से 20 21 से 30 31 से 40 और 41 से 50 जो विभिन्न प्रकार की सुरक्षाओं से संबंधित हैं के अंतर्गत आती है। सुरक्ष के प्रबंध के लिये प्रबंधक को नोटिस और अन्य कार्रवाई क्यों नहीं की गई। यदि उन पटाखों की सैकड़ो इकाईयां पंजीबद्ध नहीं थी तो उन पर न्यायालय में प्रकरण पेश किये जाने चाहिये थे। दूसरी और श्रम विभाग मे निरिक्षकों द्वारा पूर्व में मासिक वसूली की जाती थी। बाद में आवंटित क्षेत्र के निरिक्षक को कुछ फैक्ट्री मालिकों ने घेर के मारा पीटी की थी। इसलिये श्रम निरिक्षकों ने वहां जाना बंद कर दिया था। श्रम विभाग की मुख्यालय इंदौर में होने के बावजूद भी पूरा आयुक्त से लेकर नीचे निरिक्षकों तक का पूरा स्टाफ कितना निकंम्मा है राऊ की बारूद फैक्ट्री में लगी आग और उसमें मरे 13 वर्ष के आसपास का एक लड़का जो फैक्ट्री में श्रमिक के रूप में कार्यरत था सिद्ध करता है कि बाल श्रमिकों की फैक्ट्रीयों मे घातक बारूद को छोटे फटाकों अनार की मटकियों में रस्सी बमों व अन्य सभी प्रकार के फटाकों फुलझड़ियों चकरी राकेट आदि में रु. 50 से 80-90 रुपये की मजदूरी में हजारों बच्चे ही भरते हैं। अकेले राऊ में ही 100 से 150 घरेलू ईकाईयों मे हजारों बच्चे ही यह कार्य सम्पन्न करते हैं। अन्यथा रुपये 145 प्रतिदिन की कलेक्टर श्रमिक भुगतान दरों में फैक्ट्री मालिक फैक्ट्री चला ही नहीं सकता चाहे वो फैक्ट्री अनुक्षप्ति धारी हो या न होकर अवैध ही क्यों न हो

पूरे मप्र मे कम से कम पांच लाख बच्चे 8 से 18 वर्ष तक की उम्र तक के बाल श्रमिकों के रूप में कार्यरत है। जो न केवल फटाकों बीड़ी खिलौने खदानों निर्माण कार्यो चाख खड़िया खेती व अन्य सैकड़ो कार्यो में संलग्न होकर जीवन व्यापन करते हैं। इसके विपरीत इंदौर श्रमायुक्त कार्यालय में बैठे मक्कार धूर्तो को निरिक्षक सहायक उपायुक्तों के माध्यम से पैसा मिल जाता है। इसलिए इन्हे बाल श्रमिक दिखते तो हैं बेशक पर कागजी आंकड़ों में एक भी बाल श्रमिक कहीं भी बेगार और मजदूरी नहीं कर रहा है। ये झूठी और जालसाजी जानकारियां मप्र श्रम मंत्रालय से लेकर पूरी अर्थात अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन भेजी जाती हैं। बाल श्रमिकों के नाम से आया सारा धन कागजों पर ही हजम कर लिया जाता है।

बाल श्रमिकों को न केवल घातक रासायनों से लेकर होटलों घरेलू कार्यो एकल संयुक्त परिवार साझेदारी निजी कंपनियों तक मे वृहद सार पर छोटे में हानिकारक कार्यो में उपयोग किया जाता है। इसमें बाल श्रमिकों का न तो केवल घोर शोषण होता है। वरन उनका शारिरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। काम और जीवन यापन की विवशताओं में उलझकर उन में शिक्षा के आभाव के साथ पेशेवर बुराईयां बीड़ी पीना शराब और नशाखोरी की आदतें भी विकसित होती हैं। यह सब जानकर भी श्रम निरीक्षक श्रम कानूनों की आड़ मे केवल कागजी खानापूर्ती कर महीना वसूली करते हुए श्रमिकों का पर्याप्त वेतन से भी आधा वेतन अकेले इंदौर की ही पोलोग्राउँड सांवेर रोड, लक्ष्मी नगर, मांगलियां एबीरोड की निरंजनपुर, शीलनाथकेंप उद्योग नगर पालदा से नेमावर रोड की सैकड़ों फैक्टरियों में दिया जाता है। बाल मजदूरों की हालत और भी खराब है। श्रमिकों के लिये भारत में 54 अधिनियम है। इसके विपरीत उद्योग दुकान फैक्ट्री मालिक महीना बांटकर शोषण के लिए स्वतंत्र हैं।

बेशक सार्वजनिक कंपनियो में शोषण कम होता है। पर श्रम कानूनों का पूरा पालन कोई भी नहीं करता साथ ही अब ठेका श्रमिकों को भी पूरी छूट है। इससे श्रमिक ठेकेदार उनका न केवल लाभ 10 से 25प्रतीशत तक मजदूरी हजम कर जाता है दूसरी ओर नियोक्ता अपनी सारी श्रम कानूनों में वर्णित जिम्मेदारियों मजदूरी भुगतान छुट्टियों क्षतिपूर्ति आदि से बच लेता है। वैसे भी सहायक आयुक्तों उपआयुक्तों अपर आयुक्त जैसे एल के पांडे आदि को इंदौर में बैठे ही वर्षो हो चुके हैं। जो भारी ढीठ और निकम्मे हो चुके हैं। फिर फैक्ट्रीमालिक को टुकड़ों से ही निरिक्षक से लेकर उपायुक्तों तक सब पलते हैं। बेशक कोई भी रुपये 10-20 करोड़ की मालिक तो नहीं बन पाया स्वाभिवक है कि इस विभाग का उद्देश्य श्रमिक हितो का संरक्षण तो नहीं वरन श्रमिकों के हितों के संरक्षण के नाम पर वसूली करने का हथियार तो है।

सूचना का अधिकार वयस्कता से पूर्व ही हत्या पर उतारू

पेज 1 का शेष

बस जिस जानकारी को कंप्यूटर पर तैयार किया जा रहा है उसे साइट पर चढ़ाने में मिनट भर भी नहीं परन्तु जब हर विभाग की कार्य पद्धती का मूल मंत्र ही जालसाजी और भ्रष्टाचार हो तो कौन सा श्वान अधिकारी साइट प्रतिदिन उपकृत करेगा अन्ना को इसके लिये भी आंदोलन करना था। अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखें। जहां आवेदन को इस अधि. के अंतर्गत आवेदन देने पर भी 99 प्रतीशत केन्द्रीय और राज्यों के विभागीय कर्मचारियों अधिकारियों ने जागलसाजियों के नए कीर्तिमान रच लिये है। उस पर भी कई विभाग जैसे की ग्राणीण यांत्रिकीय पंचायत सचिवालय के दिशा निद्रेशानुसार लोक सूचना अधिकारी निम्न श्रेणी लिपिक को बना दिया है। जो कार्यपालन यंत्री को अपीलीय अधिकारी बना दिया गया है। ताकि उपयंत्री सहायक यंत्री और कार्यपालन यंत्री अरबों रु का भ्रष्टाचार भी करें तो भी सूचना देने से बचा जा सकता है। यही हाल मुख्यकार्य पालन अधिकारी जिला पंचायत का कृषि विभाग का भी है। ऐसी सैंकड़ों जालसाजियां इस परिपालन में मुख्यसचिवालय से लेकर की जा रही हैं। दूसरी किस्म की जालसाजी में ज्यादा शातिर निगमों निकायों कंपनियों मे बैठी है। इन सूकरों ने अपनी साइटों पर तो जानकारी डाली ही नहीं साथ ही सूचना के अधिकार में आवेदन देने पर भी ये विद्युत कंपनी लि औद्योगिक निगम म.प्र राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम आदि जैसे अनेको विभाग भोपाल में स्थित सभी विभागों के मुख्यालय संचानालय सचिवालय, प्रधानसचिवालय तक चाहे वो राज्यों के हों या केन्द्र के 29 वें दिन से लेकर 45वें दिन तक पुरानी तारीखों में जवाब भेजते हैं। यदि आवेदन सूचना के अधिकार का ज्ञानी और शिक्षित हुआ तो अपील फाईल करेगा। यदि अपील नहीं सुनेंगा जिसे आपने आवेदन दिया था। अब स्वाभाविक है कि अपने और उसके अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों अधिकारियों के विरूद्ध तो फैसला नहीं क्यों कि उस अधिकारी को उन्ही कर्मचारी और अधिकारियों के बीच बैठना है। इस लिए मुश्किल से ही आवेदक के पक्ष में फैसला देगा

अब यदि आवेदक ने दूसरी और अंतिम अपील लगाई भी तो क्या हो ना है सूचना आयोग मे साल दो साल तो नंबर ही नहीं आऐगा। मप्र का आयोग से लेकर सभी राज्यों के सूचना आयोगो में और केन्द्रीय सूचना आयोग में चारों तरफ भ्रष्ट हरामखोर और भ्रष्ट जालसाज बैठे हैं। जिनका एक मात्र मूल्य उद्देश्य है अनावेदको की अंधभक्ति और पैसा वसूलना जो एक मात्र सूचना आयुक्त पत्रकार महेश बाजपेयी बैठाये भी गये थे। तो उन्हें सीधे अपील सुनने का मौका दूसरो की अपेक्ष 10 से 20 प्रतीशत ही मिलता था। फिर जिन सरकारी भ्रष्टों की सेवा निवृत्ति के बाद बैठाया था। वर उनकी ईमानदारी व योग्यता देख कर नहीं वरन मुख्य मंत्री मुख्यसचिव व राज्यपाल से मिलकर उनके पुराने भ्रष्टाचार के चापलूसी के इतिहास को देखकर ही सूचना आयुक्तों और मुख्य सूचना आयुक्तों को बैठाया गया था। ताकि भविष्य में तो सरकार को ईमानदारी से न्याय करके मुश्किल में न डाले बेचारे पालतू श्वान का काम अपने मालिको पर भौकना तो नहीं फिर पैसा आवेदक नहीं अनावेदक सरकारी अधिकारी ही देगा। तो कैसे उसको परेशानी में डालने वाला निर्णय दिया सकता है।

इन हरामखोर सूचना अधिकार के कर्मचारियों और अधिकारियों की जालसाजी के हर कदम पर नमूनों के सबसे पहले तो अपीलों की आवक करने में ही डेढ़ से दो माह का समय लगाना दूसरा उसके उसके पंजीयन की जानकारी भेजना तो ठीक नहीं भेजी तो ठीक और यदि पंजीयन करने का अहसान किया भी तो किसके विरूद्ध कौन से प्रकरण की अपील का पंजीयन किया ये धूर्तो की फौज वह भी उल्लेख नहीं करती चौथा पंजीयन करने से पूर्व ही अनावेदकों से संपर्क कर वसूली की व्यवस्था करना अगर वसूली हो गई तो कैसा पंजीयन डाक नहीं मिला। लोकायुक्त आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो की तरह यदि प्रकरण पंजियन से पूर्व ही सौदा मनमर्जी के हिसाब से हो गया तो कौन सी कैसी अपील? प्राप्त ही नहीं हुई। कार्यालय को सैंकड़ो अपीले रोज आती हैं। फिर आवेदक के बाप के नौकर हैं क्या? जो उनकी हर बात मानी जाए। अब आवेदक इनकी शिकायत कहां करेगा। क्यों की अपील का पंजीयन ही नहीं हुआ तो खारिज करने और सुनवाई का प्रश्न ही नहीं क्यों कि दमदार और पैसों वाला आवेदक खारिज होने के बाद न्यायालय की शरण में जाकर जानकारी का प्रयास करेंगा। पर जब द्वितीय अपील पंजीयन ही नहीं हुई तो न तो सुनवाई होगी और न ही खारिज करने का प्रश्न उठता है। क्यों कि जब द्वितीय अपील खारिज होने का पत्र नहीं मिलेगा तब तक न्यायालय जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। सू.आ, इकबाल एहमद के भ्रष्टाचार और लूट के किस्से जिन्हें भूतपूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने उनके घरेलू संबंधो के चलते सूचना आयुक्त बनाया था। समय माया ने छापे ही हैं। ये भी आजमगड़िया है।

जिसे अनावेदक से धन मिल जाता है तो हरामखोर आवेदको को डांटने फटकारने से भी नहीं चूकता। पिछले छः वर्षो में इन हरामखोर सेपृष्ठों कि किस धारा 19 (8) में क्षतिपूर्ती दिलाई और धारा 19 (8) में से रुपये 250 का प्रतिदिन का दंड किया इस शूकर ने तो प्रदेश के सभी प्रथम अपीलीय अधिकारियों को सभी प्रकार के दंड देने से भी रोक दिया जब कि सूचना अधिकार अधि. 05 में जो अधिकार सूचना आयुक्त को दिये हैं। वही पूरे क्षतिपूर्ती के अधिकार प्रथम अपीलीय अधिकारी को भी दिये गए हैं। पर प्रश्न यह है कि जब प्रथम अपीलीय अधिकारी ने ही यदि प्रथम अपीलीय दंड और क्षतिपूर्ती के अधिकार का उपयोग कर निराकरण कर दिया तो इन भुखेरे श्वानों को द्वितीय अपीलीय कौन भेजेगा? ये बेचारे भ्रष्टाचार की क्रीम कहां से चाटेंगे?

6 वर्ष बाद भी संभाग स्तर पर सूचना आयुक्त नहीं की गई है। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त का पद खाली है। धारा 4 का पालन स्वयं मुख्यमंत्रीयों और प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं किया देश की स्थिती समझी जा सकती है। फिर भी इस अधिनियम के लागू होने से और सरकार का के भ्रष्टाचार सामने आने से सारी राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार के प्रधानमंत्री कानूनमंत्री वीरप्पा मोईली अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सलमान खुर्शीद तो इस कानून को समाप्त करने की तैयारी में लग गए थे। जब ज्यादा विरोध हुई तो संशोधन की कोशिश की गई। जैसे सत्ता इनके बाप की जागीर हो।

समय डॉट काम की साइट से जब यह तथ्य कि सत्ता बाप की जागीर नहीं जनता को जनता के पैसों का हिसाब क्यों नहीं दोगे। अपने भ्रष्टाचार और डकैतियों की सच्चाई सामने आते देख और उससे फजीहत के कारण गिद्दो की फौज कानून को समाप्त करना चाहती है लिखकर सभी राष्ट्रों के दूतावासों सी एन एन बीबीसी से लेकर सभी समाचार चैनलों को भेजा गया। तो अगले दिन सुबह से ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से लेकर सब के सुर बदल गए। सभी एक सुर में अलाप अलापने लगे नहीं हमारा कोई इरादा नहीं।

जबकि 6 वर्ष अभी भी सत्र और जिला न्यायालय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय तक अपने आप को इससे बाहर रखकर जानकारी नहीं देते हैं। और दलीलें देते हैं। जिनका दायित्व है कानूनों का पालन वे ही कानून की सबसे ज्यादा धज्जियां बिखेर रहे हैं। जब कि न्यायालयों में चाहे वो राष्ट्र के जिला सत्र न्यायालय हो उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय जिसकी चर्चा आए दिन समाचार पत्रों में क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्र स्तर पर होती है।जब कि न्यायालयों में हर तरफ कैमरें हो कम से कम न्यायप्रणाली को पूर्ण रूप से पारदर्शी हो ताकि जनता का विश्वास जमा रहे और आने वाली पीढ़िया वर्तमान के इतिहास को गाली न दें।

पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय के आर नारायण की टिप्पणी कि न्यायालय न्याय के मंदिर नहीं जुए के अड्डे हैं। जो जितना बड़ा दांव खेलेगा उतना ही पाएगा। न्यायालयीक व्यवस्था में पर्याप्त सुधार और पारदर्शिता का आभाव हैं।

साप्ताहिक समय माया

भारतीय रिजर्व बैंक का नाटक 0.25% बढ़ाना
1% गृह ऋण पर अनुदान

सरकारें भ्रष्ट जालसाज उद्योगपतियों की रखैल

बर्बाद करने पर तुले हैं छोटे और मध्यमवर्गीय व्यापारियों को कांग्रेसी गिद्ध

भारत के केन्द्रीय और राज्यों की सत्ता भ्रष्ट जालसाज उद्योगपतियों और पूंजीपतियों से मोटा कमीशन डकार कर उनकी रखैलों की तरह काम कर रहे हैं। उनके इशारों पर न सिर्फ पेट्रोल डीजल ईंधन गैसों की कीमतें वरन बिजगी मोबाईल दरों से लेकर बैंको की ब्याज दरें तरल नकदी प्राप्त करने जमा पर ब्याज दरें बढ़ाने और घटाने का खेल कानून बनाने परमाणु समझौता करने यहां तक कि आयात निर्यात मौद्रिक विनियम दरों तक का खेल भी इन्हीं पूंजीपतियों के इशारे पर होता है।

भारत में अंबानी बंधुओं आईटीसी जैसे भ्रष्ट जालसाजों के लिये खाद्य सुरक्षा और स्तर अधि.06 तक बना दिया ताकि सारे खाद्य व्यवसाय यहां तक कि शब्जी फल फ्रूट से लेकर पूरा दलहन तिलहन अनाज तक की सारी खाद्य वस्तुओं पर इनका कब्जा हो जाए। छोटे व्यापारी विक्रेताओं जिनमें ठेले वालों से लेकर 5 करोड़ लोग जो सड़क के किनारे व्यवसाय करने वालों से लेकर छोटे मोटे दाल मिलों तेल फैक्ट्रीयों आदि तक सब अपना व्यापार बंद करके इन भ्रष्टों रिलायंस आईडिया से लेकर पारले टाटा व अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे वालमाई वेक्ट्रातेल आदि के शरणं गच्छामी हो जाएं उन साज साजों से ये केन्द्र और राज्य की सरकारें चाहे तो कांग्रेस की हो भाजपा सबको मोटा कमीशन मिलता रहे। और ये पैकेट्स में कुछ भी मिलावटी सड़ा धुना अपनी मनमानी की कीमतों पर जनता को बेंच कर दोनों हाथों से मोटी वसूली करते हैं।

मान. प्र मं. मनमोहन सिंह प्रण लेने सच से मुकरने वाला वित्त मंत्री महंगाई के नाम पर घड़ियाली आंसु बहाकर भारतीय रिजर्व बैंक से ब्याज दरों में बढ़ोत्री करवा कर अब 0.25 प्रतीशत ब्याज दरें बढ़ा दी अब रेपोरेट बढ़ा दिया अब केश रिजर्व रेटिओ बढ़ा दिया इन सबका उद्देश्य वास्तविकता में महंगाई घटाना तो बिल्कुल नहीं वरन पूंजीपतियों और बड़े उद्योगपतियों के इशारे पर छोटे मध्मवर्गीय व्यापारियों के ब्याज दरों से कमर तोड़कर उनका व्यवसाय बंद करवाना ही है। ताकि सारा माल रिलायंस टाटा आईटीसी जैसे जालसाज खरीद सके। उन्हें 0.25 प्रतीशत ब्याज दरों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके विपरीत वह सारी ब्याज दरें और शासकीय लूट की वसूली जनता से अपने माल की कीमतें बढ़ा कर कर सकें। इसके विपरीत छोटे मझौले ब्याज दरों की बढ़ोत्तरी और बाजार की गलाकाट प्रतियोगिता में इन बड़ों से टकराने या व्यवसाय करने की हिम्मत नहीं कर सकेंगे। और मैदान छोड़ देंगे। तब भी फायदा रिलायंस टाटा और आईटीसी को ही होगा जिसके टुकड़ो. पर ये सारे सत्ताधीश पलते हैं।

वास्तविकता में चांडाल चौकड़ी मनमोहन सिंह, प्रणव,शरद पवांर, चिदंबरम को महंगाई कम नहीं करना हो पर नाटक तो करना ही पड़ेगा। क्यों की जनता की जेबों पर तो डाका ये ही डाल रहे हैं। आखिर क्यों नहीं खाद्यानों जिसमें अनाज तथा गेंहू चावल मक्का ज्वार बाजरा आदि दलहन तुअर मूंग उड़द मसूर मोंगर आदि और तिलहन मूंगफली सरसों सोयाबीन करड़ी अलसी सूरज मुखी आदि पर बैक ऋण नहीं दिया जाएगा। जमाखोरी की 2. खाद्यानों पर सहाबंदी करने की 3. देश की खपत की खाद्यान की मात्रा से अधिक को निर्यात की घोषणा करतो जो मूल महंगाई का कारण हैं। पर इसके उपर से गिद्दों की फौज कभी बात नहीं करती है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी बिरला टाटा आईटीसी कमाई से इनके कमीश बंधे हुए हैं। 0.25 प्रतीशत ब्याज दरें बैंकर्स बढ़ाना चाहें तो बढ़ायेंगे अन्यथा हजारों करोड़ों का ऋण लेने वाले पहले से ही बैंको के एम डी व अध्यक्षों को जेब में लेकर चलते हैं।और मोटा कमीशन और करोड़ की मोटी टिप मारते हैं। अर्थात मरेंगे तो लघु और मध्यमवर्गीय व्यवसायी ही जिन्हें ये पूंजीपती और बहुराष्ट्रीय कंपनियां पहले से बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ताकि ये सभी खाद्य वस्तुओं पर एकाधिकार स्थापित कर जनता को तरीके से लूटें और शोषण कर सकें

1 प्रतीशत अनुदान रुपये 15 लाख तक के मकानों के व्याज पर देने की घोषणा भी केवल बड़ी हाउसिंग और कालोनाइजिंग कंपनियों और एजेंसियों जिनसे इन्हें करोड़ों रु का चंदा और कमीशन मिलने के साथ ही बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों का पैसा इन कालोनाइजर्स बिल्डर्स और भूमाफियाओं के साथ दो ने का कालाधन विनियोजित है लाभ पहुंचाने और जनता को फंसाने का षडयंत्र का हिस्सा है। ताकि गरीबी रेखा से ऊपर निम्म मध्यमवर्गीय अपने घर के सपने् को सच करने के लिये रुपये 5 से 15 लाख रुपयों की मकानों की खरीदी में इन भूमाफियाओं भवन निर्माताओं और कालोनाइजर्स से 1 प्रतीशत अनुदान के लालच में अपना धन या ऋणों से मकान खरीद कर इन नेताओं अधितकारियों के साथ इनके शार्गिद गुडों जिन्होंने औने पौने दामों में जमीन खरीद सरकारी जमीनों खेती की जमीनों पर नगर नगर नियोजित किये हैं।

अर्थात इन कांग्रेसी गिरोह ने सब जगह पहले अपना ही भला और फायदा ही देखा है।

परीक्षाओं से हो शीघ्र भर्तियां और पदोन्नतियां

पेज 1 का शेष

मात्र एक दो से काम चलाया जा सकता है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति कृषि विभाग पंजीयन आदिमजाति कल्याण विद्युत मंडल की कंपनियो हाउसिंग बोर्ड पंचायत एवं ग्रामीण विकास कोषालयों आबकारी सहकारिता खनिज आदि सभी विभागों में जहां निरिक्षकों की पदस्थापनाएं है। कम से कम 2 हजार निरीक्षक जिसमें शिक्षा खाद्य आपूर्ति पंचायत राजस्व खनिज श्रम औद्योगित स्वा. एवं सुरक्षा आदि में 1 लाख बाबुओं की जहां आवश्यकता हो छोटे अधिकारियों की आवश्कता है। जिनकी भर्ती शीघ्र की जाना चाहिये।

अन्यथा 70 प्रतीशत तक स्टाफ सन 2015 तक सेवानिवृत्त हो जायेगा। जिससे प्रशासनिक आवश्यकताए चरमरा जाएंगी। जबकि हर विभाग में 20 वर्षो में अनेको योजनाएं कार्य प्रारंभ होचुके हैं। और उसे संपन्न करने के लिए स्टाफ की मंहती आवश्यकता होती है। जो कि न्यूनतम के कारण पुराने घाघ हो चुके कर्मचारी संपन्न कम करते हैं और भ्रष्टाचार ज्यादा।

इस राष्ट्र को मिश्रित अर्थव्यवस्था पर चलने वाला लोकतंत्र ही रहने दिया जाए पूंजीपतियों बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कठपुतली न बनाया जाए। अन्यथा परिणाम अमेरिका ब्रिटेन यूरोपिय देशों मे हो रहे आंदोलनों से समझा जा सकता है।

लोकतंत्र जनकल्याण तंत्र होता है। डकैत तंत्र नहीं उस जनता के लोग अगर शासन में ही नहीं होंगे जो होंगे वो पूंजीपतियों की रखेल तो कैसा लोकतंत्र होगा फिर शासन को चलाने के लिये अधिकरियों और कर्मचारियों की भर्तीकर वर्तमान भाजपा सरकार 3 लाख युवाओं की और उनके 8 लाख परिजनों की दुआएं लेकर अगले 10 वर्ष आसानी से शासन कर सकेगी जब अभी से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी तो परीक्षायें साक्षात्कार लेते लेते वर्ष गुजर जायेगा।

दूसरी और जब सर्वोच्च न्यायालय ने इंजी. राकेश शर्मा म.प्र लोक निर्माण विभाग विरूद्ध म.प्र शासन में यह स्पष्ट निर्णय दे दिया है कि पदोन्नतियों मे केवल वरिष्ठता ही चलेगी आरक्षण का लाभ भर्ती के समय दे दिया जाता है तो सभी विभागों में सभी वर्गो को एक समान वरिष्ठता के हिसाब से पदोन्नत किया जाना चाहिए जब कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन 100 से ज्यादा सभी विभागों में म.प्र. शासन की धूर्त आई ए एस लाबी ने नहीं किया।

इसके विपरीत कनिष्ठता वरिष्ठता आरक्षण और बेकलॉग सब तत्काल बंद करो हर विभाग में बाबू अधिकारियों इंजीनियरों डॉक्टरों से लेकर हर किसी की हर दूसरे वर्ष परीक्षओं का आयोजन किया जाकर जो 50 प्रतीशत या कटआफ मार्कस लाए उसे पदोन्नत करो जनता का पैसा बाप की जागीर नहीं और प्रशासन कबाड़ी का मैदान नहीं जिस पर कोई भी बैठ कर जनता को धन से वेतन लेकर मौज उड़ाये उसे कुछ भी आता जाता न हो और पद के योग्य न हो जिससे जनता परेशान हो और प्रशासन भी और भविष्य की पीढ़ी में भ्रष्टाचार निकंमेपन का संदेश जाये देश का भविष्य जातियों से नहीं ठोस कार्य करने आधार मजबूत करने से चलेगा। व्यर्थ के वोट बैंक को सिर पर बैठाने से नहीं यहां विश्व की प्रतिस्पर्धा याद नहीं आती अधिकारी योग्य शिक्षित और कार्यशील हो न कि नकारा निकंमे और बकवास में समय बर्बाद करने वाले।

वेतन 365 दिन का काम 180 दिन से भी कम फिर भी छूट

बंद करो शनि. की छुट्टी जिस माह दो छुट्टियां हों

जनता 365 दिन काम करे, सरकारें लूटे खायें मौज मनायें

भारत में केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों के अधिकारियों कर्मचारियों को सरकार अनाप शनाप जनता से महंगाई बढ़ाकर जिसमें पेट्रोल डीजल की कीमतों से लेकर जिसमें 38 प्रतिशत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में कस्टम एक्साइज के साथ ही 2 प्रतिशत सड़क रखरखाव निर्माण शुल्क जो सन 1986 से वसूला जा रहा है। 2 प्रतिशत शिक्षा उपकर और 2 प्रतिशत उपकर शामिल है। बेइंतहा कीमतें बढ़ा कर अपने खर्च चलाती है। जिसमें केन्द्र सरकार के सभी विभागों के मंत्रियों संत्रियों केन्द्र सरकार के सभी विभागों के मंत्रियों संत्रियों अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन 365 दिन का जबकि काम मात्र 180 से ज्यादा नहीं करना पड़ता जिसमें 12 रविवार और शनिवार को मिलाकर 104 दिन की छुट्टियाँ वर्ष भर में 3 राष्ट्रीय अवकाशों के साथ त्यौहारों की औसतन 15 से 18 दिन छुट्टियां भी मिलती हैं। अर्थात 125 दिन की तो सरकार ही छुट्टी देती है। फिर 12 आकस्मिक 15 चिकित्सा और 33 अर्जित अवकाश मिलाकर 60 दिन चिकित्सा और 33 अर्जित अवकाश मिलाकर 60 दिन अर्थात 185 दिन की तो शासकीय वैधानिक छुट्टियों पुरुषों को और महिलाओं को गर्भावकाश की 3 माह पूर्व और पश्चात 3 माह 6 माह का भी वैचारिक अवकाश दिया जाता है। यही हाल गर्भपात में भी है जबकि निजी संस्थानों से लेकर नीचे तक महिलाओं को ऐसी अवस्था में अवैचारिक करने के साथ हटा दिया जाता है। इसलिये 15 दिन पूर्व और 25 दिन पश्चात ही काम पर लौट आती हैं। जबकि खेतिहर निर्माण कार्यो या रोजनदारी की महिला मजदूर जिन्हें रु. 50 से रु. 70 रोज मिलते हैं 10 दिन के बच्चों को 2-3 फटे चिथड़ों मे लपेटकर रेत के खलिहान या खेत के घासपूस वाले स्थान पर पटक बेचारी मजदूरी कर अपना और बच्चों का पेट भरती है।

इसके विपरीत सरकारी चाहे तो केन्द्र सरकार के कार्यालय हों या राज्य सरकारों के कार्यालयों से लेकर दूर दराज के स्कूलों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों जो गांवो में होते हैं। 70 प्रतिशत महिला कर्मचारियों का हाल यह है कि वे बचे हुए 180 दिन में से भी बहानाबाजी कर उनमें से केवल घंटे दो घंटे कार्यालयों स्कूलों स्वास्थ्य केन्द्रों में विलंब से पहुंचेंगी बाद में यदि 2-4 महिला कर्मचारी अधिकारी है तो फिर गप्पों घरेलू चर्चाओं का दौर शुरू एक सवा बजते ही टिफिन और लंच का दौर शुरू जो ये कामचोर मक्कार तीन बजे तक पूरा करती हैं। इसके साथ ही 180 दिनों में से 3 ऐच्छीक अवकाशों के साथ ही कम से कम महीने में दो पांच दिन कार्यालय में शक्ल दिखानें हाजिरी पर हस्ताक्षर करने ही आती हैं। और बोस से बड़े बाबू से अधिक यदि उस महिला कर्मचारी अधिकारी की खूबसूरती पर लट्टू हैं। तो फिर सारा कार्यालय नाड़े से कई कार्यालयों में तो महिलाओं के अपने अधिकारियों बड़े अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक से संबंध होते हैं। तो केवल महीने में एक बार ही पूरे माह की हाजिरी भर हस्ताक्षर कर वेतन खाते में जमा हो जाता है। अर्थात जनाता से करों में महंगाई बिजली पानी सड़कों व अन्य सेवाओं सामग्री पर भारी करारोपण कर ये सरकारी अधिकारी मंत्री सरकारें सत्ता को अपने बाप की जांगीरी समझ कर कैसे लूटते हैं और बिना काम लुटाते हैं। सरकार की छुट्टियों की नीतियों का खुला उदाहरण हैं कि 365 दिन के वेतन में मात्र 180 दिन से भी कम काम करो भ्रष्टाचार करो लूटो जनता को निचोड़ों और जन धन से रंगरैलियां मनाओं जनता के 25 प्रतिशत को एक वक्त और 25 प्रतिशत को दो वक्त की रोटी मुश्किल से नसीब हो, पर सत्ताधीश धूर्तो को इससे क्या फर्क पड़ता है। चुने हुए को जनता वोट देने वाले जनवरों और चयनितों के लिये नाली के कीड़े मकोड़ो से ज्यादा क्या है। इसी जनता के दम पर सत्ता मे बैठकर भी 365 दिन का वेतन लेकर भी 180 दिन भी काम नहीं करना चाहते हैं। उनके नाम पर लाखों करोड़ों रुपये की बंदरबाट कर हजम कर जाते हैं। ये चुने हुए और चयनितों की फौज जो शुकरों खानों और गिद्दों सेभी ज्यादा निम्न मानसिकता की है अजगरों की भांति केवल कुर्सी से चिपक कर केवल मैके की तलाश में हजम करने के आदि हैं।

यदि केन्द्र की सत्ता और राज्य की सत्ताओं में बैठे हरामखोरों की फौज में जरा भी नैतिकता बची हो तो जिस सप्ताह में त्यौहारों की छुट्टियां पड़े उस सप्ताह में शनिवार की छुट्टियां न दी जाएं। दूसरा अर्जित अवकाश भी घटा कर साल में 15 दिन से ज्यादा न दिया जाए तीसरा महिलाओं को प्रसव पूर्व एक माह और प्रसव पश्चात 45 दिन सेज्यादा वेतनिक अवकाश न दिये जाए अन्यथा अर्जित और चिकित्सा अवकाश में जो खाते में हो समायोजित किये जाए पांचवां जिस वर्ष प्रसव अवकाश दिया जाए मेडिकल और अर्जित अवकाश की उस वर्ष पात्रता समाप्त की जाए।

ऐच्छिक अवकास समाप्त किये जाए जिसे त्यौहार मनाना है आकस्मिक अर्जित अवकाश से छुट्टियां दी जाए। सत्ता बाप की जांगीर नहीं जिसे अपनी तरह से हांका जाऐगा। जनता से उसकी मेहनत की कमाई को जो अनाप शनाप करारोपण से वसूला जा रहा है और सत्ता में बैठे धूर्तो प्रधान मंत्री मंत्री मुख्यमंत्री सचिवों से लेकर शासकीय पदों पर बैठे चपरासी तक अपने मन चाहे तरीकों से वेतन पत्रों में प्राप्त कर वर्ष में आधे दिन भी काम न कर पूरे वर्ष का वेतन लेकर हजम करते जायें अन्ना का आंदोलन पूरा मस्तिष्क पर आ चुका है ऐसा न हो कि आने वाले समय में जनता ये भी मांग करे कि मात्र रविवार के अवकाश के अतिरक्त शासकीय कर्मचारियों अधिकारियों मंत्रियों सचिवों को वर्ष में किसी प्रकार के अवकाश न दिये जाएं। आखिर अंग्रेजों के बनाए इन कानूनों में क्या परिवर्तन होगा। वो तो विदेशी शासक था जिनका उद्देश्य वसूला और केवल मौज मस्ती ही करना ही था। अब तो देश को आजाद हुये 65 वर्ष हो चुके हैं। फिर ये कैसा शासक वर्ग है कि जनता 365 दिन काम करके भी दो वक्त की रोटी मुश्किल से इकट्ठी कर पाये और शासकीय गिद्दो की फौज मात्र 180 दिन ही काम करके मौज मस्ती और आराम की जिंदगी बिताए।

90 प्रतीशत पैसा हजम कर लिया जाता है उद्यानिकी में

फर्जी आंकड़ो और फल फूलों व मसालों की खेती

करोड़ो रुपये डकारे जा रहे हैं, मंत्री और मुख्यमंत्री कागजी आंकड़ों पर इठला रहे हैं

म.प्र. शासन के कुछ विभाग सिर्फ कागजी आंकड़ों की खानापूर्ती कर धन हजम कर रहे हैं। जिन पर शासन हर वर्ष अरबों रुपये खर्च करता है। बदले में परिणाम शून्य होता है। जैसे कि पशु विभाग केन्द्र और राज्य का रु. 800 करोड़ कागजों पर ही चल रहा है। वरना रुपये 100 प्रती जानवर भी बढ़ता तो हर वर्ष 80 लाख दूधारू जानवर बढ़ना चाहिए थे। यदि 80 लाख जानवर बढ़ते तो दूध ही इतना होता कि जनता दूध से नहाती तो भी समाप्त नहीं होता। पर प्रदेश में 60 प्रतीशत दूध नकली और मिलावटी तो 100 प्रतीशत सांची और अमूल बेंच रहे हैं। शासन के मक्कान शरामखोर व धूर्त श्वान मंत्री से लेकर गांवों में कागजों पर बैठाया गया डॉक्टर तक सब लूट में लगे हैं। ऐसे विभाग में रेशम संचानालय मत्स्य आदि तो दूसरी तरफ कुछ विभागों का काम जिसमें उद्यानिकी विकीरण सुरक्षा आयुक्त निः शक्तजन आदिम जाति अनुसंधान व विकास संस्थान स्वराज संस्थान आदि,ऐसे विभागों में केवल खानापूर्ती कर वहां बैठे संचालक उपसंचालक सहा. संचालक तकनीकि अधिकारी लेखापाल और बड़े बाबू छोटे बाबू मिलकर अरबों रुपये हजम कर रहे हैं।

अकेले उद्यानिकी और वानिकी विभाग में रुपये 1500 करोड़ से ज्यादा प्रतिवर्ष बर्बादी की जाती है। जिसमें केन्द्र की राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन और राज्य की योजनाओं में वहां बैठे सहायक संचालक लेखाकार और बड़े बाबू और तकनीकि कर्मचारी मिलकर हजम कर जाते हैं। सयुंक्त संचालक पांडे इंदौर के यहां पड़े छापे तथ्यों की सच्चाई बयान करते हैं। देवास का संचालक यू एस शाक्य और इंदौर का उद्यानिकी प्रभारी जिसे जिसे राऊ विधायक जिराती के दबाव के चलते इंदौर का प्रभारी बनाया गया। हामड़ भ्रष्टाचार और लापरवाही के चलते निलंबित है। देवास में ग्रा. विकास उद्यानिकी के रूप में तकनीकी शारण को ग्रा. उद्यान विकास अधिकारी आइएम बरगोदे जो पूर्व में अप्रैल 2011 तक तोमर देख रहा था। जो वर्तमान में शाजापुर में पदस्थ है। जून अगस्त तक यहां सहायक संचालक शाक्य पदस्थ था। इन चारों में मिलकर रुपये 14 लाख अनु. जाति के रुपये 10 लाख कुल रकम एक करोड़ 31 लाख में से रुपये एक करोड़ हजम कर गए और झूठे बिलों से भुगतान करवा दिये गए। यह व्यय 9-10 का था जब तोमर और शाक्य थे राष्ट्रीय कृषि विभाग के रु. 8.65 लाख में से रुपये 8 लाख रुपये 2,86,1001 के बड़े शहरों के आस पास उद्यानिकी मिशन में पूरा रुपये 2.50 लाख कुल रुपये एक करोड़ 68 लाख 94 हजार में मात्र रु 150 इन तीनों हरामखोरों ने हजम कर लिया।

5 नर्सरियों मल्हार देवास, हरनावदा, खजूरियाकलां, बेड़ामऊ और चंद्रकेशर में बाटी गई। मजदूरी रुपये 11 लाख में से वहां के उद्यानिकी प्रभारियों ने गरीब दैनिक वेतन भोगियों की छुट्टी और रुपये दो ढाई हजार प्रतिमाह भुगतान कर 9-10 में से 3 लाख हजम कर लिये। 9-10 में से रुपये 4 लाख 74 हजार में से भी रुपये ढ़ाई लाख हजम कर लिये गये।

सूक्ष्म सिचाई में फरंग तक रु. 1.53 करोड़ में से रुपये एक करोड़ 20 लाख हजम कर लिये गये मार्च में रु 45 लाख 76 हजार में से रुपये 35 से 40 लाख इन तीनों शाक्य बड़गोदें और मालवीय ने मिलकर डकार झूठे व्हाउचर लगाकर भुगतान कर दिया गया। जब कि दूसरी परियोजना आलू विकास मिर्ची धनिया पत्ता गोभी गिलकी भिंडी आदि फलों आम केला अमरूद आंवला नींबू संतरा आदि फूलों में गलाब गेंदा आदि औषधियों में भी नर्सरियों मे खेतों घरेलू बागवानी किचन बागवानी शहरों के आसपास बागवानी मिशन आदि में केन्द्र और राज्यों का मिलाकर रुपये दो से तीन करोड़ आदिवासी अनु. जाती के नाम से आवंटन प्राप्त है कुल खर्च का 90 प्रतीशत पैसा इन तीनों धूर्तो 10-11 ने डकारा

1 जून 11 को उज्जैन उद्यानिकी सहा संचालक श्रीवास्तव ने अपनी निरीक्षण टीम में आरोप तो नहीं लगाये पर बताया कि मिसन योजना में रोकड़ का शेष रु.16,04,937/- है। पर विभाग की पास बुक में 31 तीन 11 को शेष रु. 59,79,681 रु बता रहा है। यह स्पष्ट करता है कि विभाग की रोकड़ में झूठे बिलों व्हाउचरों से खर्चे दिलवारकर शेष दिखा दिया गया है। परन्तुवह पैसा वस्तविकता में खर्च ही नहीं हुआ है। जिसे चोर के भाई गिरहकट ए डी श्रीवास्तव उज्जैन ने बहुत हल्के में लिया। पूरे म.प्र में सूक्ष्म सिचाई के नाम पर रुपये एक अरब बीस करोड़ से ज्यादा की बंदरबाट की गई है। प्रदेश के 50 जिलों में हर सहायक संचालक ने रुपये 2 से 3 करोड़ के फर्जीवाड़े से हजम कर लिये जिसका मंत्री कैलाश विजयवर्गीय है।

मार्च 11 में मेला प्रचार में रुपये 1 लाख में 90 हजार हजम प्रशिक्षण में रुपये 53400 में से 45000 हजम कृषि विकास योजना के रुपये 21 लाख 39 हजार में से रु. 18 लाख डकारे कृषक भ्रमण प्रशि. के रु. 1.50 हजार में से रुपये 1 लाख डकारे सूक्ष्म सिंचाई के रुपये 96 लाख में से रुपये 90 लाख हजम किये गये। इस प्रकार रु. एक करोड़ 25 लाख से ज्यादा हजम करके एडी सुभाष श्रीवास्तव स्थांनतरण पर भोपाल मुख्यालय में पदस्थ हो गये।

ये था मद 78 का खर्च मद 64 में संकर मिर्ची के रुपये 3 लाख में रु. 2.9लाख कृषि विकास रु. 6 लाख 39 हजार में से रुपये 6 लाख, कृषक प्रशिक्षण में रुपये 38 हजार में से रुपये 25000/- सुक्ष्म सिचाई के रु. सात लाख में से रु. 6 लाख, उद्यानिकी मिशन के रुपये 5.25 लाख में से रु. 4.9 लाख डकारे गये अर्थात मद 64 का रुपये 20.55 लाख डकार लिया गया।

शीर्ष 41 उद्यानिकी (आयोजना) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में खर्च रुपये 8,58 हजार में से रुपये 8 लाख कृषक प्रशिक्षण 37000 में से रु. 22 हजार उद्यानिकी मिशन रु. 2,62 हजार में से रु. 2 लाख कुल रु. 10.25 लाख हजम कर लिये गये। शीर्ष 74 उद्यानिकी आयोजना में आलू विकास में खर्च रुपये 2 लाख में से रुपये 1.80 लाख फूल पौधारोपण योजना में रुपये 6.22 लाख में से रुपये 5 लाख बड़े शहरों के आसपास के खर्च रुपये 4.65 लाख में से रुपये 4.50 लाख घरेलू बागवानी रु. 2.49 लाख मे से रुपये 2 लाख औषधीय एवं सुगंधित फसलों के रूपये 5 लाख खर्च में से 4.90 लाख मसाला विकास योजना खर्च में रुपये 1.35 लाख में से रुपये 1 लाख अर्थात रुपये 37.70 लाख रुपये हजम कर लिये गए। शीर्ष 15 में रुपये 6.60 लाख यहां बैठे कर्मचारी अधिकारी हर वर्ष रुपये 2 से 4 करोड़ हजम कर जाते हैं। इसकी कोई भी तकनीकी जांच की व्यवस्था नहीं होने से चारों तरफ लूट का आलम है। लोकायुक्त मैदानी हकीकत जानकर आसानी से पूरे प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारी से लेकर मंत्री तक जांच शुरू कर सकता है।

सेल फोन, विद्युत, बैंको, बीमा आदि को लूट की पूरी छूट

लोक अदालतों की दहशत देकर कार्पोरेट क्रिमिनल्स की वसूली

19 नवंबर 11 को हुई लोकअदालत में चारों तरफ कंपनियों के अधिकारी थे

भारत के भूतपूर्व प्रथम नागरिक और राष्ट्रपति स्व, के आर नारायणन ने 25/1/2001 को भारतीय न्यायालयीन व्यवस्था के बारे में कहा था-

''न्यायालय न्याय के मंदिर नहीं जुए के अड्डे हैं जो जितना बड़ा दांव खेलेगा उसे उतना न्याय मिलेगा''

भारत में पैर पसारता पूंजीवाद अब पूरा राष्ट्र और उसकी सभी व्यवस्थाओं को संभाल रही है। राष्ट्र का प्रधानमंत्री मनमोहन से लेकर उससे जुड़ी राष्ट्र की सारी व्यवस्थाएं इन पूंजीपतियों की रखैल बन चुकी हैं। अब धूर्त अंबानी टाटा बिरला भारती जैसे सैकड़ों पूजीपतियों सत्ताधीशों सांसदों को मंत्रियों विधयकों को खरीदकर कानून बनवाते हैं। लोकअदालतें चलाते हैं। जनता को चमकाते हैं। और जनता को नोंच खाते हैं। और जनता है कि बस इस सारे हरामखोरों के जाल में उलझ कर रह जाती है। कभी इकट्ठी होकर सच्चाई की बात नहीं कर पाती है। अंत में गाने की वह लाईन याद आती है कि न तू हिन्दू रहेगा न मुसलमान रहेगा गुलाम की औलाद है गुलाम रहेगा। अर्थात हजारों वर्ष की गुलामी झेल चुकी ये जनता अब भारतीय पूजीपतियों का गुलाम होकर उनका शोषण झेल रही है। तो मात्र एकजुट न हो सकने साच को सच न कहने के कारण

19/11/11 को लगी अदालत नहीं यथार्थ में वसूली मेला थी। बेशक जनता को नोटिस लोकअदालत के नाम से ही भेजे गए थे। जब कि पूरे अदालत परिसर मे विद्युत मंडल के ही सबसे ज्यादा काउंटर थे। बिलों के भुगतान के संबंध में तोड़बट्टे करके भुगतान प्राप्त कर रहे थे। अब सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि न्यायालय परिसर मे न्यायालय के नाम पर विद्युत मंडल की पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी लि. के कर्मचारी और अधिकारी कैसे सच और झूठ अधिक बिल का जनता या उपभोक्ता के पक्ष में तो निर्धारण करेंगे नहीं कमरे के निवास में जबकि हीटर कूलर फ्रीज टीवी कुछ नहीं है मात्र पंखा और एक सीएफएल जलाई है इसके विपरीत इसका बिल हजारों में आ रहा है। अब कितना कम लोगे बिल। 50000 रुपये के बिल को रुपये 200 जब कि यह भी अधिक है तो नहीं किया जा सकता उपभोक्ता की कमाई भी रुपये 3 से 4 हजार महीना है। उसका सामर्थ्य नहीं कि वह टीवी कूलर फ्रिज चला सके। इसके विपरीत उसका मीटर 80 किमी की स्पीड से बिना पंखा और बल्ब जलाए भाग रहा है। तो

कैसे और कौन भुगतान करेगा। पर अदालत की सील सिक्के से नोटिस समझौते का आया है। तो बेचारा उपभोक्ता जो हजारों की संख्या में थे दौड़कर आये पर वहां मालूम पड़ा कि सभी कंपनियों के ही कर्मचारी हैं। जो अपनी मर्जी से और कंपनियों के हित में ही वसूली कर रहे हैं।

दूसरी तरफ इंदौर न्यायालय के बगीचे में भारत दूरसंचार निगम लि. ने अपना डेरा जमा रखा था। सारे कर्मचारी अधिकारी भ्रष्ट शूकर निकम्मा लि.के ही थे। एक नोटिस समय माया के वायर लेस लोकल लूप था जिसे निगम को 06 मार्च 10 को समर्पित कर दिया गया था इसके बाद अप्रैल 10 से लगातार बिल भेजे जाते रहे। जिसकी शिकायत जीएम पियूष खरे से लेकर नीचे तक के अधिकारियों तक को की जाती है। पर ये शूकरों की फौज ने बिल भेजना बंद नहीं किया। पहले नोटिस भेजा वकील से बात की इसके बाद कार्यालय जाकर उस फोन के समर्पण की रसीद दिखाई इसके बाद भी न्यायालय स्थायी और निरंतर लोक अदालत जिला न्यायालय जिला इंदौर (लीगल सर्विसेस अथॉरिटी एक्ट 1987 का धारा 19(5) एवं 20 के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी स्थायी लोकअदालत खंड पीठ क्र.1 व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 इंदौर की मुद्रा के साथ नोटिस भेज दिया। जिसमें भारत शासन की शेर की मुद्रा नहीं थी। जहां खंडपीठ क्र एक का कागज चिपका था जब उस कक्ष में प्रवेश किया तो वहां डॉ शरद पंडित और का. अ. एपी राने भी बैठे थे जब पीठासीन अधिकारी ये पत्र दिखाया गया तो उन्होंने पुनः बीएसएनएल के डेरे में भेज दिया। अतः यह फर्जी ढंग से संगठित डकैतों की अदालत थी जिनमें इन संगठिक पूंजीपतियों की लूट जो वास्तविकता में उपभोक्ताओं को अनाप शनाप बिल और उस में मनमानी लूट करना चाहते हैं। यदि उपभोक्ता इनकी चालबाजियों में नहीं फंसा तो उसे इस प्रकार अदालतों का भय दिखाकर लूट लिया जाता है। यही हाल एचडीएफसी, इंड्सबैंक, आईसीआईसीआई,स्टेट बैंक आदि का था। जिसमें पहले उसे ऋण डेबिड क्रेडिट कार्ड दिये फिर उस पर मनमाना ब्याज सेवाआदि शुल्क ठोंक कर उसके चैक लौटवादिये फिर लोकअदालतों का भय दिखाकर घसीटा गया परेशान किया गया। अर्थात संगठित पूंजीपति कंपनियां जनता को लूटे और उसके सामने जनता लुटने से मना करे तो अदालती झगड़े में डालकर उसका जीना हराम कर दें।

अमेरिका ब्रिटेन और अधिकांश यूरोपीय राष्ट्रों में इन पूंजीपतियों संगठित अपराधियों जो जनता का चहुं दिशि शोषण कर अपने खजाने भर रहे हैं। जनता ने बिगुल बगावत का फूंक दिया है।

विश्व व्यापार संगठन की आंड़ में भारतीय सत्ताधीश अपना लाखों करोड़ कमीशन डकार कर जनता को इन सफेद पोश कार्पोरेट क्रिमिनल के हांथो में गिरवी रख रही है। उनके हितों में कानून बनाए जा रहे हैं। आवश्यकता है जनता के जागरूक होकर एकत्रित होने की राष्ट्र की बर्बादी रोकने की अर्थात आने वाले कल में ये कार्पोरेट क्रिमिनल राष्ट्र की सत्ता को पूर्णतः हांकने लगेंगे। कानून पुलिस सब इनकी रखैल हो जाएगा। वर्तमान मे भी अंशतः न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका सब इनकी रखैल है। अंबानी बंधु देश का बजट तक अपने हिसाब से बनवाते हैं। मनमोहन की सरकार ही क्या पूरा विपक्ष भी उनका खरीदा हुआ है। खाद्य से संबंधित सारे कानून उनके हिसाब से बनाये जा रहे हैं। जनहित के लिये नहीं बची खुची सच्चाई इन लोकअदालतों के नाम से पूरे राष्ट्र में सामने आ रही है।

जिस गिद्ध ने 10वर्ष प्रदेश नोंचा अब देश नोंचेंगे

दिग्गी दानव, राहुल का सलाहकार सबका बंटाघर

अर्जुन ने राजीव को निपटाया, दिग्गी निपटाएंगे राहुल को

राष्ट्र की राजनीति में मप्र के दो महाधूर्त मुख्यमंत्रियों से स्व. अर्जुनसिंह और जीवित दिग्गी दानव में, उनके भ्रष्टाचारों, लूट खसोट, डकैती, दानवीय प्रवृत्ति में बेलॉग भोंकने अपने कुकृत्यों, भ्रष्टाचारों को ढांकने, अय्याश प्रकृति, प्रदेश को, उसकी जनता को, राक्षसों की भांति नोंचने में अत्यधिक समानताएं थी और हैं।

स्व. अर्जुन ने मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश की कपड़ा मिलों को लूट, वसूली और अपना हिस्सा मांगने पर नहीं मिला तो इंदौर, उज्जैन, रतलाम, बुरहानपुर की अन्य जिलों की कपड़ा मिलों में लाखों लोगों को बेरोजगार कर तालाबंदी करवा दी, जिनकी परिसंपत्तियों की लूट खसोट 20-20 वर्षों के बाद भी जारी है। लॉटरी खिलवा कर प्रदेश के करोड़ों लोगों से अरबों रुपए डकारे गए, जब हलफनामा तो जांच कमीशन बैठा दिया चुरहट का जांच कमीशन वर्षों बैठा रहा, जांच पूरी नहीं हुई चुरहट का डकैत जरूर पूरा हो गया। 1994 से फिर दिग्गी दानव ने मप्र की सत्ता संभाली जो खजाना भर भाजपा गई थी उसको पूरा लूटा और फिर कर्मचारियों तक को वेतन बांटने के लिए जब देखें तब ओवर ड्राफ्ट लिया जाता रहा, अब जबसे फिर भाजपा सत्ता में आई तो उसने तो अभी तक और ड्राफ्ट नहीं लिया। प्रदेश की सड़कों का केन्द्र से मिलने वाला केंद्रीय सड़क निधी, मंडी, एडीबी, आदि साथ प्रदेश का भी हजारों करोड़ हजम कर लिया जाता था, रखरखाव का पैसा हजम होने के कारण सारे राज्य के राजमार्गों पर सन् पूरा होते होते ओरी लगानी शुरू कर दी। मप्र सड़क परिवहन निगम 5000 से ज्यादा बसों के रखरखाव का, उसकी कमाई को लगभग हजार करोड़ हर वर्ष हकारा जाता रहा, इसी दानव के समय ही बसें खणीदी दिखाकर निजी बसों को ठेके पर लगाया जाने का उन निजी बसों की कमाई भी हजम की जाने लगी, स्वाभाविक या बस मालिकों ने बसें हटा ली और इस तरह निजी बस मालिकों से परमिट देने के नाम पर भी खुलकर हजारों करोड़ का खेल कर, सड़क परिवहन निगम बंद कर दिया गया निजी बस मालिकों जिनमें अधिकांश नेताओं, पुलिस अधिकारियों की बसें ही थी, जनता को लूटने और शोषण के लिए निजी बस वालों को खुला छोड़ दिया गया।

इसके सत्ता संभालने से पूर्व तक मप्र विद्युत मंडल लाभ में चल रहा था, इस डकैत के सत्ता संभालते ही डकैती डालने से 1994 से लगातार हर वर्ष दो दो बिजली की कीमतें बढ़ाकर जनता को लूटा जाने लगा कोयला की चोरी करवाई जाने लगी, स्वाभाविक या मंडल घाटे में जाने लगा, दिल लूट से फिर भी नहीं भरा तो इलेक्ट्रानिक भी जो मात्र रुपए 120 का था 200 में अपने भाई को फर्म से खरीद कर, जो कि यांत्रिक मीटर से 50 से 200 तक तेज रीडिंग दिखाते थे। करोड़ मीटर बदले गये रुपए 800 करोड़ भी को खाने के बाद पुराने मीटरों भी बेंच कर पैसा हजम कर गया, ट्रांसफार्मर, लाइनों से लेकर अधिकारियों, कर्मचारियों की पोस्टिंग स्थानांतरण सबसे रुपए 1000 करोड़ की व्यवस्था इसे चाहिए थी, इसके बाद में अपने कुकर्मों का ढांकने उसे 5 कंपनियों में बांट दिया ताकि लूट और डकैती का हल्ला नहीं मचे इस प्रकार प्रदेश को अंधेरे में डूबो दिया जिन फैक्ट्रीयों, व्यावसायियों ने अपने जनरेटर्स लगवा लिए इस श्वान ने उस पर भी करारोपण कर वसूली लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय में जनता को जल आपूर्ति के नाम पर नगर निगमों, पालिकाओं, परिषदों तक से पैसा हजम किया न तो बिजली के बिलों का अरबों रुपए चुकाया गया, न ही जो पैसा केन्द्र व राज्य सरकार को आवंटित बिलों का पैसा हो दिया गया, नई योजनाओं पाईप लाइनों, टंकियों तक में से पैसा हजम किया गया जो हजारों करोड़ में होता था। उल्टे ही नाबार्ड, एडीबी से भी ऋण लिया गया सब से ज्यादा विश्व बैंक से कर्जा लिया गया वह पैसा भी इस दानव ने हजम कर लिया।

वन विभाग में लूट का तांडव

मप्र वन विभाग हर वर्ष 2000 करोड़ अमेरिकी डालर विश्व वन्य प्राणी निधि से मिलते थे, इस रुपए 1 लाख करोड़ का एक पैसा कभी जमीन पर खर्च नहीं किया गया। सारा पैसा ऊपर ही ऊपर हजम कर लिया जाता था, और अभी भी भाजपा सरकार इसे झूठे आंकड़ों की बाजीगरों से हजम कर रही है। सन् 1991 से वन विभाग में 927 शेर और 1851 तेंदुएं 20 वर्ष बाद भी यथावत हैं। इस बात की सच्चाई जब 1999 को समय माया ने छापी तो यह समाचार मार्च 1999 को लंदन के समाचार में और भारत के टासम्स ऑफ इंडिया में अप्रेल 1999 में यथावत छाप दिया गया था, जिससे 1999, 2000 और 2001 में इन भुखमरों को विश्व वन्य प्राणी निधि से अ.डालर 2000 करोड़ नहीं मिले, तब से समय माया की लेखनी का ज्ञान पूरे मप्र की सरकार को हो गया था। अविभाजित मप्र के जंगलों से इस हरामखोर दिग्गी दानव ने 1995 96 से लेकर 2003 तक लगातार वनों की कटाई करवाकर लगभग 5000 करोड़ पेड़ कटवा कर इसने गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश व देश के अन्य मांगों में बिकवा दिये, जिसमें बेशकीमती सागौन, बबूल, जैसी सैकड़ों प्रजाति के 12-15 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के पेडों को कटवा कर इसने बिकवा दिया और लगभग 20 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों की बर्बादी की। जिसकी खबरों के फोटो जिसमें लकड़ी से भरे ट्रक, ट्रालों आदि को वर्षों तक छापा गया, पर इस राक्षस को कोई फर्क नहीं पड़ा, 10 वर्ष के शासन काल में मप्र के

110 से ज्यादा विभागों का लगभग केन्द्र और राज्य का फिर चरनोई की जमीनें तक बेचकर छग की खनिज संपदाओं को बेंच, गिरवी रखकर बड़ी लगभग 10-12 नदी घाटी परियोजनाओं जिसमें नर्मदा घाटी, हासदेव बांधों, बेतला महानदी आदि परियोजनाओं तक का लगभग 30 लाख करोड़, जिसमें लाख करोड़ से ज्यादा की विदेशी सहायता विश्व बैंक एडीबी का ऋण, नाबार्ड बाजार छग से लेकर पूरे मप्र को चौपट किया।

यहां तक कि कारगिल का लगभग रुपए 500 करोड़ से ज्यादा का चंदा तक हजम कर लिया गया, जबकि मप्र के सरकारी कर्मचारियों ने दो दिन का वेतन जो रुपए 70 करोड़ था वह धूर्त दानव हजम कर गया था जिसका सामचार समयमाया ने अगस्त 99 में छापा, शीतकालीन सत्र वर्तमान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और स्व. लक्ष्मण सिंह गौड़ ने 31/10/99 को जब यह समाचार पत्र विधानसभा में लहराया और सवाल किए तो हंगामा हो गया और विधानसभा रद्द करना पड़ी बाद में 1 नवंबर को यह विधानसभा में फिर उठा, तो फिर विधानसभा में हंगामा हुआ, और 1 बजे के बाद विधानसभा में जब जनसंपर्क मंत्री से पूछा गया कि कुल कितना धन इकट्ठा हुआ तो जवाब मिला मात्र रुपए 9 करोड़ 36 लाख, तो फिर श्री अजमेरा ने पूछा केन्द्र का धन आपने अपने पास क्यों रखा तो जवाब दिया गया मप्र के सैनिकों को रुपए 10 लाख प्रति सैनिक बांटा जाएगा। फिर पूछा कि कितने सैनिक मरे तो जवाब था कि 11 अर्थात रुपए 1 करोड़ 10 लाख ही बांटे गए, जबकि स्कूलों से रुपए 50 करोड़ का चंदा दूध मुंहों से लेकर कालेज के विद्यार्थियों तक सेंक्शन किया गया। फिर परिवहन विभाग का रुपए 30 करोड़ आबकारी 30 करोड़, वाणिज्यिकर रुपए 25 करोड़ लोक निर्माण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय, ठेकेदारों से रुपए 20 करोड़ जलसंसाधन से 25 करोह, खाद्यएवं नागरिक आपूर्ति, से रुपए 25 करोड़, विद्युत मंडल से रुपए 20 करोड़, आदिम जाति कल्याण से रुपए 35 करोड़ इस प्रकार सभी विभागों से रुपए 5 से 30-40 करोड़ जिसमें जितना आवक थी वसूला करके हजम कर लिया गया, इस समाचार के छपने के कारण बाद में 1 नवंबर से 5 नवंबर 99 तक विधानसभा दिग्गी दानव ने स्थगित कर दी थी। प्रदेश के 50 से ज्यादा जिलों में बैठाए गए कलेक्टरों से रुपए 1 से 10 करो तक प्रतिमाह वसूले जाने थे, हर मलाईदार पोस्ट से महीना हर स्थानांतरण और पोस्टिंग से कमाई का उद्योग इसी के शासन काल में विकसित हुआ, सुधा मिश्रा हत्याकांड में इसके खास लोगों ने जलाने के बाद ये ही राज्य के विमान से दिल्ली लेकर गए थे। इनके 10 वर्ष के शासनकाल में भ्रष्टाचार की 10-20 हजार पन्नों की पुस्तक लिखी जा सकती है। इसी की कांग्रेस पार्टी के विधायकों को विधानसभा में इसके सामने आकर राजा साहब कहकर पहले पैर छूते थे, और बाद में बोलते थे कि ये दिग्गी राजा नहीं दानव है। यह दानव पूरा प्रदेश नोंच खाएगा, इसी के विधायकों का उवाच है दिग्गी दानव। इसकी चांडाल चौकड़ी में तथाकथित आईएएम इकबाल सिंग बैस, सुधि रंजन मोहंती जैसे डकैत थे जिन्होंने जहां कदम रखे बर्बादी की दास्तां ही लिखी।

इस कलियुगी दानव के सामने सतयुग के रावण जैसे दानव भी इसकी लूटने और बर्बाद करने की रणनीति को देख इसकी चेला गिरी करते। इसकी अय्याशी के चलते ही नाब तहसीलदार सलीना सिंग सूरज डामोर जैसे भ्रष्ट महिलाओं को जिनमें तहसीलदार बनने तक की योग्यता नहीं थी जल ही आईएएस तक बना दिया गया। अब यदि ऐसे धूर्त दानव अगर राहुल के सलाहकार होंगे तो क्या हाल राहुल अगर प्रधानमंत्री बन ही गया तो देश के हालतों का समझा जा सकता है। जो हाल स्व. राजीव का भूतपूर्व स्व. मुख्यमंत्री अर्जुनसिंग ने किया था। शायद कहीं हाल राहुल का करवाएगा, उसको कुछ समझेगा नहीं और उसकी आड़ में यह श्वान देश को नोंच खाएगा। वर्तमान में भी अपनी काली कमीज जो भ्रष्टाचार और बदतमीजी और कुकर्मों से बनी सनी है। यदि कोई अंगुली उठाता है तो अपनी वहीं धूर्तता पूर्ण बदतमीजी का कीचड़ उछालकर उसकी कमीज भी काली करने पर तुल जाता है। फिर भी इसे सलाहकार बनाया गया तो पूरी कांग्रेस ही जनता को नफरत का शिकार हो जाएगी राष्ट्रीय स्तर पर।

व्यापारिक औद्योगिक सहकारी बैंक लि., इन्दौर
महादेव शाहरा सभागृह, नई अनाज मंडी, संयोगितागंज, इन्दौर
फोन : 2477755-2477766, 4084827
सहकारिता सप्ताह पर हार्दिक अभिनंदन
गोपालदास अग्रवाल
अध्यक्ष
मोहनलाल सैनी उपाध्यक्ष
महेन्द्रसिंह राजपाल प्रबंधक
श्रीमती सीमा मंगल उपाध्यक्ष
-संचालकगण-

सहकारिता सप्ताह के अवसर पर सभी सम्मानीय सदस्यों-सहयोगियों एवं सहकारी मित्रों को
हार्दिक शुभकामनाएं..
हार्दिक बधाई...
सुकल्या ग्राम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित
(पंजीयन क्रं. I.R.U.D.R. 296 दिनांक 02.05.1981)
भगवानसिंह बेलिया
अध्यक्ष
रमेश जैन
35/ए, दीनदयाल उपाध्याय नगर, सुकल्या ग्राम, इन्दौर
फोन : 0731-2550133

श्री छत्रपति शिवाजी सहकारी साख संस्था मर्या. इन्दौर
(म. प्र. सहकारी संस्था अधिनियम 1960 की धारा के अंतर्गत पंजीकृत)
सहकारी सप्ताह पर संस्था से जुड़े सभी सदस्यों को
हार्दिक शुभकामनाएं
-पदाधिकारी-
-संचालकगण-

अन्नदाता किसानों के हक में
एक और बड़ा फैसला
1 अप्रैल 2011 से प्रदेश के किसानों को
1% ब्याज दर पर फसल ऋण
50 लाख किसानों को दस हजार करोड़ के फसल ऋण वितरण का लक्ष्य

श्री शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री म.प्र. शासन

श्री गौरीशंकर बिसेन
मंत्री, सहकारिता म.प्र. शासन
किसान हृदय सम्राट मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किसानों को 1% ब्याज दर पर कृषि ऋण मुहैया कराने का ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय लेकर कृषकों और कृषि क्षेत्र की तरक्की और खुशहाली का नया अध्याय लिखकर "किसान युग" की शुरुआत की है।
भँवरसिंह शेखावत
अध्यक्ष,
अपेक्स बैंक

अपेक्स बैंक
म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या.
(सशक्त सहकारिता, समृद्ध मध्यप्रदेश)

पेट्रोल में मची है लूट, मंत्रालय से पंपों तक सबको छूट

7 वर्ष में दुगुनी कीमतें- रोना घाटे का

हर कंपनी को हजारों करोड़ का फायदा, सत्ता नाचती हैं रिलायंस के इशारे पर

राष्ट्र की सत्ता में अंबानी बंधुओं और टाटा का बोलबाला है तो जैसा चाहते हैं, सत्ताधीश प्र.म. मन मोहन, पेट्रोलियम मंत्री जयपाल रेड्डी वैसा ही नाचते हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी कंपनियों तेल एवं प्राकृतिक जैसे आयोग ओएनजीसी को 08 -09 में रुपए 16126 करोड़ 09-10 में 16767 करोड़, 10-11 में 18924 करोड़ का लाभ इंडियन आइल को 08-09 में रुपए 2949.56 करोड़, 09-10 में 10220.55 करोड़ और 10-11 में रुपए 7445.48 करोड़ का लाभ हुआ, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम को 08-09 रुपए 574.98 करोड़, 09-10 में रुपए 1301.37 करोड़ और 10-11 में रुपए 1539.01 करोड़ का लाभ हुआ भारत पेट्रोलियम को 08-09 में रुपए 735.9 करोड़, 09-10 में रुपए 1537.62 करोड़ का और 10-11 में रुपए 1546.98 करोड़ का लाभ हुआ। ये सरकारी आंकड़े पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा ही जारी किये गये हैं। अर्थात पेट्रोलियम मंत्रालय से लेकर पेट्रोल पंपों के हॉकरों तक का वेतन रुपए 4500 होगा।

पर कमाई रुपए 40-50 हजार प्रति माह तक की है। बेशक हॉकरों की कमाई पेट्रोल की नाप को चोरी से ही होती है। स्वाभाविक है कि पेट्रोल पंप मालिक प्रति ली. मिलावट और कमीशन मिलाकर रुपए 5 से लेकर 25 प्रति ली. तक कमाता है। हर पेट्रोल पंप मालिक टर्न ओवर के हिसाब से कंपनियों के विक्रय प्रबंधक सेलेकर जिले के खाद्य नियंत्रक, नापतोल खाद्य, निरीक्षकों को भी रुपए 5-10 हजार प्रतिमाह तक बांटना है। अर्थात नीचे से लेकर ऊपर तक दोनों हाथ लूट में लगे हैं।

इसके बाद भी रोना घाटे का, घाटा तो मात्र जनता को हो रहा है। भारत का पेट्रोलियम मंत्रालय, प्र.मं. मनमोहन तक सब रिलायंस पेट्रोलियम जिसकी जामनगर प्रतिदिन 1.4 से 1.6 लाख बैरल जो शासन के रिकार्ड में है। जिस पर रिलायंस टेक्स चुकाता है वास्तविकता में ढाई से तीन लाख बैरल प्रति दिन का उत्पादन है, जिसे भारत, इंडियन आइल और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम इसकी ही बिक्री करते हैं। मथुरा और असम की रिफायनरी का तेल अधिकांश रक्षा मंत्रालय को जाता है।

भारत के सत्ताधीशों की नीति पूंजीपतियों का लाभ और गरीबों को मिटाने के लिए गरीबों से लूट कर रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय इसका श्रेष्ठ उदाहरण है कि अमीरों के लिए हवाई जहाज में लगने वाला 100 अक्टेन से ज्यादा का पेट्रोल तो मात्र रुपए 59 प्रति लीटर है जबकि 58 आक्टेन का पेट्रोल रुपए 71 से ज्यादा प्रति लीटर है जो जनता मोटर सायकलों और कारों में उपयोग करती है। सत्ताधीश डकैतों की ये फौज प्रति लीटर पेट्रोल पर रुपए 59 प्रति लीटर का टैक्स वसूलती है, राज्य व केन्द्र सरकार जिसमें 2% सड़क सेस 2 % शिक्षा सेस 2% सेवा सेस भी जनता से ही वसूला जाता है। इस पर भी ये रोना कि पेट्रोल पर अनुदान सरकार को देना पड़ता है। इनके तो बाप पूंजीपतियों हवाई जहाज उड़ाते हैं, या हवाई जहाजों में उड़ते हैं। उन्हें उससे दुगुने आवंटन का पेट्रोल क्यों मात्र 59 रुपए प्रति लीटर में बेचा जाता है। दूसरी ओर पेट्रोल पंपों पर बिकने वाला पेट्रोल 58 आक्टन का होना चाहिए जो 38-40 से ज्यादा नहीं होता और मिलावट कर देने पर 25-28 ही रह जाता है। उसके बारे में ये हरामखोर जालसाज पेट्रोल पंप कंपनियां और मंत्रालय क्यों 40 वर्षों से चुप्पी मारे बैठा है।

पेट्रोल पंपों पर कम नाप के मामले में किसी भी श्वान के मुंह से कुछ नहीं निकला कई बार तो रुपए 100 के पेट्रोल में रुपए 25 का भी पेट्रोल नहीं देते ये डकैत पेट्रोल पंप वाले इंदौर के पलासिया में मूलथान के कर्मचारियों की जालसाजियों के बारे में कहां जाता था, तो उन्होंने श्री अजमेरा को एक दिन केवल मीटर घुमाकर रुपए 100 तो झटक लिए पर पेट्रोल 300 मिग्रा भी नहीं डाला अर्थात पूरे देश में जनता कैसे से इन पंपों पर लूट रही हैं, कोई भी नाप तोल के निरीक्षकों, मिलावट के मामले में खाद्य निरीक्षकों तक सबको नहीं न मिलता है, इसलिए कोई कुछ नहीं कहता और जनता लुप्ती रहती है। इसके बाद भी कीमतों में लगातार बढ़ोत्री हो रही है। जो अभी रुपए 2 कम भी किए हैं। शीतकालीन लोकसभा सत्र और यूपी के चुनावों के मद्देनजर।

98% शासकीय कार्यालय बंद 27,28,29 अक्टूबर 11 को

सरकारी नौकरी खूब छुट्टियां कार्यालय नहीं धर्मशाला

जन धन से वेतन लेने वाले महा बेशर्म और निकम्मे

भारत में दीपावली का त्यौहार एक बड़ा त्यौहार होता है, इसमें कोई शक नहीं, 15 दिन पहले से तैयारी और 15 दिन बाद तक सुरुर छाया रहता है। पर इस सुरुर का असर भारत में केन्द्र और राज्य सरकार के 150 से ज्यादा विभागों पर कुछ जरूरत से ज्यादा छा जाता है। इसके पीछे दो महत्वपूर्ण कारण होते हैं। कि एक तो हरामखोरी और भ्रष्टाचार से इकट्ठा धन, खर्च करने का और अड़ोस-पड़ोस में, समाज में खरीदी मिठाई और फटाके फोड़ने के स्तर से दिखाने का भरपूर मौका दूसरा कार्य के 6 से 8 घंटे सीमित होने के साथ ही राज्य सरकारों में छुट्टी का आवेदन रखकर सामूहिक रूप से गायब होने की व्यवस्था भी हो जाती है। सरकारी कर्मचारी अधिकारी, पुलिस आदि की छोड़ दें तो 365 दिन का वेतन लेकर 180 दिन भी काम करना नहीं चाहते जबकि 185 दिन की तो छुट्टियां मना ढील हैं। फिर भी हरामखोरी करने कार्यालयीन समय में बहाने बनाकर गायब हो जाते हैं। कैसे भी सरकारी कार्यालय कम धर्मशालायें ज्यादा हैं।

इसको देखें कि इस वर्ष मात्र 26 अक्टूबर दीपावल थी, मात्र दीवाली की ही घोषित छुट्टी थी पर अधिकांश कार्यालय 27, 28, 29 अक्टूबर को भी बंद थे, या चपरासियों ने कार्यालय खोल भी दिए थे 98% तक स्टाफ गायब था, 28 अक्टूबर 2011 को देवास जाने पर मालूम पड़ा कि अब कार्यालय सोमवार को ही खुलेंगे यहां तक कि 25 अक्टूबर 2011 की शाम से ही जिलाधीश कार्यालय में ताले डले थे, 27, 28 तक ताले डले देखकर जब मुख्यमंत्री कार्यालय से बात की गई तो बताया गया कि कहीं कोई छुट्टी नहीं है। आप को ज्यादा कुछ मालूम करना है तो मुख्य सचिव कार्यालय में फोन लगाकर मालूम कीजिए जब मुख्यमंत्री कार्यालय को फोन लगाकर पूछा गया कि क्या देवास में 27, 28, 29 अक्टूबर तक की छुट्टी है, तो जवाब मिला नहीं, कोई छुट्टी नहीं है। आप लिखित में भेजिये जब समयमाया.काम की साइट पर लोड करके सूचना मुख्यमंत्री और मुख्य कार्यालय को भेजी गई, तब प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए देवास के सारे कार्यालयों को मजबूरी में जिलाधीश मुकेश गुप्ता, एसडीएम, एडीएम ने छापे मारे तो अधिकांश कार्यालय बंद पाए गए। जबकि साजिश में स्वयं जिलाधीश स्वयं ही शामिल थे यदि उन्होंने भाईदोज की छुट्टी घोषित भी की थी तो भी 27 अक्टूबर को तो सारे कार्यालय खुलने ही चाहिए जबकि हर कार्यालय में 25 अक्टूबर 2011 शाम से ही लग गए थे। जबकि हर कार्यालय का 98 % स्टाफ गायब था, अधिकांश कार्यालयों में तालों की फोटो समयमाया.काम गेलरी में लोड हैं। पाठक चाहें और मप्र सरकार चाहे तो देख सकती है। कोषालय पर बाहर जो सिपाही खड़ा था, उसने बताया कि 25 अक्टूबर 2011 से ही ताले लगा दिये गये थे। 27 अक्टूबर को भी कोषालय के साथ पूरे जिलाधीश कार्यालय जनपद पंचायत आदिम जाती कल्याण, जिला उद्योग केन्द्र, पंजीयन कार्यालय, आदि सभी में ताले डले रहे, ये कलेक्टर मुकेश गुप्ता की साजिश का बेहतरीन नमूना है कि 27 को वो स्वयं कार्यालय सेम्पल थे 28 को छुट्टी घोषित कर दी ताकि 29 को शनिवार और 30 को रविवार तक सारा स्टाफ अघोषित छुट्टी मनाने बेशक पूरे प्रदेश में अधिकांश जिला कार्यालयों के 27 से 29 को ताले लगे रहे। और भ्रष्ट मप्र सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया, जबकि 3 दिन तक कार्यालय, कोषालय आदि बंद रहना सरकार की प्रशासनिक क्षमता और उस पर कार्यवाही न करना निकम्मेपन और अफसरशाही की घोर भ्रष्ट कार्य प्रणाली को बताता है। क्या सरकार जांच करवा कर जनता की पसीने की कमाई का रुपया 200 करोड़ से ज्यादा वेतन काटकर बचाएगी और प्रशासनिक दक्षता का जनता को सबूत देगी..?

मां ही करती है भविष्य की मां की हत्या

पेज 8 का शेष

चार बेटियों के बाप में त्रस्त होकर पूरे परिवार के साथ आत्म हत्या कर ली। जैसे समाचार अखबारों में रोज आ रहे हैं। प्रदेश का महिला बाल विकास विभाग केन्द्र और राज्य से अरबों रुपये मिलता है। परन्तु धूर्त मक्कार मंत्री रंजना बघेल से लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तक सारी कागजी खानापूर्ती कर 90 से 95 प्रतीशत तक पैसा हजम कर लिया जाता है। हर हरामखोर जिला अधिकारी चाहे तो इंदौर का कुलकर्णी जो पहले धार में था।

चाहे वे पूर्व की मंजूला तिवारी जो अब उज्जैन में है देवास की तृप्ती त्रिपाठी हो पूरे प्रदेश के हर जिले में यह विभाग लुटेरे और डकैतों का अड्डा बना है। फिर अधिकांश महिलाए जाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से लेकर आसीडीसीएस जो समान्यतः हर जिला मुख्यालय पर सहसीलों में 8 से 10 तक होती हैं।

जिला तहसील विकास खंडो के लेखा से लेकर बाबुओं तक आय से प्रतिवर्ष 10 गुना और 10- 20 वर्ष जिसने पूरे कर लिये हों। 100 से हजार गुना तक संपत्ति के मालिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तक धूर्तो और मक्कारों की फौज 2-3 मोबाइल पांच दस तोला सोना तक बदन पर लदा मिल जाएगा। आखिर कहां आसमान से टपक रहा है। हाल ही में लोकायुक्त के छापे तक लेखाकार तक करोड़ों की संपत्ति का मालिक निकला। श्वानों की फौज गरीब बच्चों और महिलाओं के विकास के मान पर खुद का विकास करने में जुटे हैं।

चप्पा कर्मचारी से लेकर सचिव प्रधान सचिव मंत्री तक आर्थिक अन्वेशण और लोकायुक्त छापे मारे तो मालूम पड़ेगा कि एख तरफ मुख्यमंत्री बेटी बचाओ आंदोलन चलाता है और दूसरी तरफ उसी का मंत्री से लेकर छोटा कर्मचारी तक कैसे जिंदा बेटियों को कैसे मारने में तुला है। दिल्ली की टीम ने इंदौर का सच सामने ला दिया है। खंडवा के खालवा का सच चाहे तब सामने आ ही जाता है। इंदौर के 8 जिलों में आदिवासी जिलों का सच और भी भयावह है। वहां भी आदिवासी विकास के नाम पर चारों तरफ अंधेरगर्दी है। पर इन पर कहीं कोई प्रभार नियंत्रित नहीं है। सुपरवाइजर तन और धन दोनों पाकर आंख मींच कर हस्ताक्षर कर देता है। संयुक्त संचालक तक की जांच रिपोर्ट समय माया पूर्व में भी प्रकाशित कर चुका है। वास्तविकता यह है कि पूरे देश का यही हाल है।

विधानसभा नहीं सत्ता के दलालों का अड्डा

पेज 8 का शेष

इस राजन नायर की एक फार्म एमपी कार्गो के नाम से है। जो स्वास्थ्य विभाग से लेकर अनेकों विभागों में औषधियों की आपूर्ती से लेकर अन्य सामग्री की आपूर्ती करती है।जो पूर्णतः फर्जी होता है। टीटी नगर थाने में इसके विरूद्ध एक अपराध पंजीबद्ध है। जिसमें इंदौर की एक फर्म से ऐथामिन नाम का एक इंजेक्शन पशु चिकित्सा आपूर्ती लेकर हमीदिया अस्पातल में प्रदाय कर दिया था जिसे डॉक्टरों ने अनेक बीमार मनुष्यों में प्रयोग किया था। सत्ता सभ्यता के प्रादुर्भाव से लेकर वर्तमान तक वे चाहे म.प्र की हो या राष्ट के अन्य सभी प्रदेशों की या केन्द्र की या विदेशों की सदा से जालसाजों चाटूकारों दल्लों अपराधियों के चंगुल में रही है। फिर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार कैसे इसका उपराध हो सकती है। इसके विपरीत बुद्धिमान शासक और और सत्ताधीश ऐसे जालसाजों चाटूकारों दल्लों अपराधियों को इनके जाल में ही उलझाकर समूल नष्ट कर जनहितों की वास्तविकता को समझें जनता के सुखद भविष्य के लिए प्रयत्नशील रहकर अपनी गरिमा बचाये और बनाये रखते हैं। देखना ये है कि मुख्यमंत्री ऐसे दल्लों पर क्या कार्रवाई करते हैं। वैसे कार्रवाई की उम्मीद निर्थक है ये रणछोड़ दास तो विधानसभा सत्र भी डर और फजीहत के डर के कारण पूरा नहीं चलाते हैं।

साप्ताहिक समय माया

कन्या भ्रूण हत्या नारी ही नारी की घोर सत्रु

मां ही करती है भविष्य की मां की हत्या

महिला बाल विकास में चारों ओर गिद्दों की फौज

पूरे राष्ट्र में नारियों की घटती संख्या हर समाज नगरों प्रदेश देश के साथ विश्व में भी बड़ी समस्या के रूप में उभर रही है। विश्व के सबसे ज्यादा आबादी के दो देश चीन और भारत में कन्याओं और कन्या भ्रूण की सबसे ज्यादा हत्या की जाती है। और यही दोनों देश ही सबसे ज्यादा स्त्रियों की कमी से सबसे ज्याद परेशान हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा मानसिक कारण है कि पुरूष वादी मानसिकता साथ ही चीन में एक जोड़ा एक बच्चे की नीति में दंपत्ति पुत्र ही चाहते हैं। जो कि भविष्य में उनका जीवन भर साथ निभा सके। दूसरी ओर भारत में स्त्री पराया धन होने के बावजूद उसे पाल पोष पढ़ा लिखाकर 20-25 वर्ष तक बड़ा करो और बाद में वो शादी करके अपने पति के साथ चली जाती है। स्वभाविक है कि वह अपने पति और उसके घर को चलाती है। जबकि पुरुष रूपी पुत्र को पाल पोस कर बड़ा करके पढ़ा लिखाकर बड़ा करने से भारतियों दंपत्तियों को उसे बुढ़ापे और जीवन भर साथ निभाने और संभालने को आशा करते हैं। इसके विपरीत सच यह भी है कि वर्तमान परिस्थितियों पुरूष रूपी पुत्र भी पढ़ लिख और बढ़ा होकर वह भी माता पिता को छोड़कर अलग रहने लगता है। और माता पिता तरसते हुए प्राण त्यागते हैं।

पुत्रों की चाहत हर दंपत्ति को इसी कारण होती है। और इसी आशा में आधुनिक जांच साधनों के चलते वह गर्भ में ही तीसरे चौथे माह से ही जांचचे करवाकर यदि कन्या भ्रूण होता है तो गर्भपात करवा लेते हैं। यह निम्न मध्यमवर्गीय से लेकर उच्च मध्यमवर्गीयों तक सब जतियों और धर्मो के साथ पूरे भारत में कश्मीर से कन्या कुमारी और मुंबई से लेकर कलकत्ता और शिलांग तक सब ही जगह विद्यमान है। अब जब कि हर दंपत्ति दो बच्चे रखकर परिवार को छोटा रखना ही चाहते हैं। यदि पहला पुत्र हो गया है तो गर्भ निरोधक का नसबंदी करवाकर दूसरी पैदा ही नहीं करते हैं। यदि पहली कन्या हो गई है तो दूसरा पुत्र की आस में ही बच्चा पैदा करते हैं। इसके लिये जो जांचे करवाते हैं। कन्या होने पर भ्रूण को गर्भपात से कोख में ही नष्ट करवा दिया जाता है।

इसका सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि पुत्र पुत्री के संबंध में पुरूष जो पिता होता से ज्यादा पुत्र की चाहत स्त्रियों की अपेक्षा दुगनी होती है। दूसरा स्त्रियों की जन्मजात दुश्मन स्त्रियां ही होती है। और स्त्रियों की इच्छा नारी की मां बनने से ज्याद पुरूष की मां बनने में नैसर्गिक आनंद जीवन भर मिलता है। जबकि स्त्री की मां बनने पर स्वयं स्त्री ही अपने आप को उतना गौरवान्वित महसूस नहीं करती। साथ ही पुरूष तो घर में एक पुत्री की कामना करता है। और यह भी सही है कि नैसर्गिता स्त्री पुरूष के आकर्षण के चलते पुत्री ही पिता को अपना सर्वमान्य महानायक मानकर भी पिता का मां से ज्यादा ख्याल रखती है। वही हाल पुत्र का होता है कि पुत्र थोड़ा भी समझदार होता है तो वह मां को पिता की अपेक्षा मां का ज्याद ख्याल रखता है। मां का पुत्र से और पुत्र का मां से आत्मीय मानसिक और भावनात्मक संबंध स्त्री को पृथ्वी पर जन्म लेने की सार्थकता के साथ ही स्त्री की घोर मानसिक संतुष्टि जीवन पर्यत देता है। कि पुत्र जन्म के बाद स्त्री का लगाव पति के ज्यादा पुत्र से ज्यादा होता है। उसकी यही सोच कन्या भ्रूण की हत्या कोख में ही करने का कारण बन जाती है। यह मानसिकता चीन और भारत की अपेक्षा अधिकांश राष्ट्रों और धर्मो में पाई जाती है।

अर्थात नारी यह जानकर भी कि नारी ही भविष्य में गर्भधारण कर मां बनेगी। फिर भी नारी ही नारी की भ्रण हत्या कोख में ही कर देती है। इसके विपरीत कन्या ही मां की सबसे बड़ी सहेली संरक्षक होने के साथ मां बेटी भी एक दूसरे की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धी भी होती है। सबसे ज्यादा मां की श्रंगार समग्री से लेकर वस्त्रों की गहनों आदि का उपयोग करती हैं। इसलिए स्त्रीयाँ भी स्वयं स्त्री जन्म को मानसिक कष्टदाई मानती हैं। वर्तमान मे मप्र सरकार का बेटी बचाओ आंदोलन चल रहा है। बेटी नहीं तो कल नहीं बेटी नहीं तो बहू नहीं के नारे लगा रहे हैं। तो दूसरी तरफ अरबों रुपये खर्च करने के बावजूद जिंदा बेटियों को नहीं बचा पा रहे हैं। (शेष पेज 7 पर)

विधानसभा में प्रश्नोत्तर में दलालों का साम्राज्य

विधानसभा नहीं सत्ता के दलालों का अड्डा

विधानसभा में जनहित नहीं दलालों के हितों के सवाल जबाब

भोपाल। म.प्र. विधान सभा के प्रश्न जमा करने में भी पक्ष विपक्ष के उन चाटूकार दलालों का साम्राज्य है जो प्रश्न लगाने के लिए रु 5 से 50हजार रुपये तक का शुल्क वशूलते हैं। साथ ही जिनके विभाग के विरूद्ध प्रश्न लगाया जाता है। उनके मंत्रियों से भी सेटिंग पर वसूली करते हैं। जिसकी कीमत 25-50 हजार रुपये से करोड़ों तक हो सकती है। कीमत मिलने पर ये जालसाज दल्ले प्रश्न वापिस ले लेते हैं। सौदा न पटने पर प्रश्न लगाकर उस मंत्री विभाग की धज्जियां विपक्ष उड़ाता है। यदि प्रश्न लगने पर विधान सभा में जवाब वाले दिन तक उस मंत्री से विधायक से लेन देन का सौदा पट गया तो जिस दिन वह प्रश्न लगा है या आने वाला है उस समय वह संबंधित विधायक विधान सभा किसी भी कारण से या अकारण भी गायब हो जाता है। विधायक चाहे पक्ष का विपक्ष का या निर्दलीय हो सारा खेल लेन देन का चलता है। कितना भी जनहित का मुद्दा हो विधायकों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसमें कोई कमाई न हो उसके लिये सभी पत्रकारों विधायक चाटूकारों व दल्लों से सदा संपर्क में रहते हैं। लेन देन के प्रश्नों को लगाने वापिस लेने और गायब रहने के लिये ये भोपाली पत्रकार चाटूकार दल्लों के साथ ही विधायकों के स्वयं चेले चपाटी या सहायक तक की सेवाएं ली जाती है। अर्थात जनता के चुने हुए प्रतिनिधी विधायक कितने बड़े चुरकट बन कर जनभावनाओं के साथ कैसा खिलवाड़ करते हैं। ये उसका बहुत छोटा सा उदारण है। इन कार्यो के लिये इन दल्लों और विधायकों के सहायकों और कुछ विश्वसनीय चालाक पत्रकारों के पास इन विधायकों के प्रश्न लगाए जाते हैं। हस्ताक्षरित परिपत्र सदा अग्रिम में ही तैयार रहते हैं।

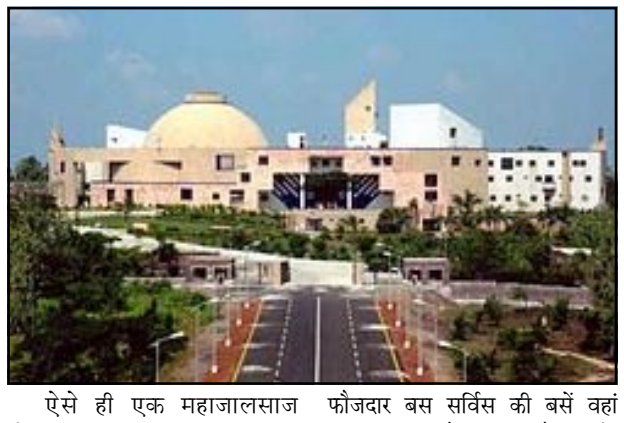

ऐसे ही एक महाजालसाज भोपाल में एक महाविद्यालय शास. चिकित्सा महाविद्यालय का भंडार गृह प्रभारी राजन नायर जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है। जो कि तृतीय श्रेमी कर्मचारी है। और अधिस्ठाता निर्भय सिंह के मुंह लगा खास व्यक्ति है। इन्ही निर्भय श्रीवास्तव के पिता जी के बारे में कहा जाता है कि वे एक साधारण पटवारी से इमानदारी और प्रतिभा के दम पर मुख्यमचिव से सेवा निवृत्त हुए थे का अधिस्ठाता बेटा इस दल्ले राजन नायर के माध्यम से पूरा पूरा चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्रालय हांकते और धन उगाही करते हैं। इस राजन नायर के पास इसी दल्लागीरी के चलते सुंदर नगर मीनाल रेसीडेंसी अन्य स्थानों पर है। इसके पास सेंट्रो कार एम पी 04 सीई 3056 जिसमें इसकी पत्नी उमा नायर का साकेत का पता डला है। सूत्रों के अनुसार संदिग्ध है। वैसे शहर के बड़े अपराधिक माफियाओं के साथ भी इसके गहरे संबंध है। इसके पास हॉट पीपल्या के विधायक दीपक जोशी व कैलाश जोशी के हस्ताक्षरित प्रश्न पत्र रहते हैं। जिनका उपयोग वो सत्ता पक्ष के मंत्रियों के लिये करता है।

ये वही दीपक कैलाश जोशी हैं जिन्होंने रा.रा मार्ग का 59 अ को कभी विकसित नहीं होंने दिया और फौजदार बस सर्विस की बसें वहां चलती रहें और इन्हें और इनके पिता जब विधायक थे चंदा मिलता रहा। इससे इंदौर हरदा मार्ग के कन्नौद खातेगांव सोना उगलने वाली धरती के तो दोनों क्षेत्र और उनसे जुड़े गांवो के विकास का मार्ग सदा से ही अवरुद्ध करके रखा, उनके ये पुत्र पिता की ख्याती का कैसा दुरुपयोग कर रहा है। यह कृत्य उसका ज्वलंत उदाहरण है। कैलाश जोशी जब भाजपा के सरकार के मंत्री थे जब स्वयं कैलाश जोशी ने भी फौजदार व अन्य बस आपरेटरों से खुद चंदे की वफादारी निभाते हुए भी कुधन किया और न होने दिया। अब जब कि खेल मंत्री तुकोजीराव पवांर म.प्र. सरकार का मंत्री देवास हाटपिपल्या मार्ग और देवास जिले का एक एबीरोड और देवास भोपाल मार्ग छोड़ दिया जाए तो सारे मार्गो के हालात बहुत ही बुरे हैं। चारों तरफ लूट और वसूली का बोलबाला है। धड़ल्ले से सारे जंगलों की कटाई और जमीनों पर कब्जे के लिये देवास जिले के सारे विधायक और मंत्री हैं। जो अपनी अय्याशी और मौज मस्ती में व्यस्त रहते हैं। जिनके हस्ताक्षरित प्रश्न पत्र भी दल्ले करते हैं। विधायक दीपक जोशी का एक चेला सहायक धर्मू तिवारी भी राजन नायर का सहयोगी रहता है।

(शेष पेज 7 पर)

घोषणा वीर, छपास रोग और आत्म प्रशंसा से पीड़ित

चारों तरफ अंधेरगर्दी और अंधेरा म.प्र में

म.प्र. में 1नव. को अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेशक दूसरे कांग्रेसी घोर भ्रष्य मंत्रियों से जिनमें मुख्य रूप से अर्जुन सिंह और दिग्गी दानव ने चारों तरफ लूट और भ्रष्टाचार के उच्चतम मानदंड स्थापित किये ये भले ही बेहतर और बहुत ही कम भ्रष्ट हों पर भ्रष्ट तो हैं।

हाल ही में मंत्री बाबूलाल गौर ने खुद स्वीकार किया कि प्रदेश में मंत्रालयों से लेकर नीचे ग्राम पंचायत स्तर तक बेलगाम अफसर शाही का बोलबाला है। ये भ्रष्ट निकम्मी और धूर्त अधिकारियों की फौज कागजी खेतों पर झूठे और फर्जी आंकड़ो का उत्पादन करती है। जिसके दम पर प्रदेश की भाजपा सरकार को मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्री तक जनता को केवल शब्ज बाग दिखाकर अपने मुंह मिट्ठू मियां बनकर अपनी बड़ी बड़ी उपलब्धियों को गिनवाते हैं। और घोषणाएँ करते हैं कि विपक्ष इन घोषणा वीरो की सच्चाईयों को व्यान करते हैं तब थोड़ा बहुत जनता समझ पाती है।

क्यों जिन सच्चाईयों को मीडिया को बताना चाहिये कि प्रिंट मीडिया एक तरफ तो पूर्ण तरह माफियाओं का गिरोह बन चुका है तो दूसरी तरफ सत्ताधीशों और पूंजीपतियों की रखैल की तरह सच छुपाकर जग के सितारों नग्नता से भरा होता है। इसके साथ यह भी सच है कि 95प्रतीशत समाचार पत्र मालिकों का उद्देश्य अपने काले धंधो का छुपाना कमाई करना होता है। उन्हें भी ज्यादा पढ़े लिखे बुद्धीमान पत्रकार नहीं, अच्छे फीटिंग पेस्टिंग चोरी के समाचार जिनसे कमाई हो, छापने वाले चाहिए होते हैं। इसलिये चाहे भास्कर हो हिन्दुस्तान टाइम्स, राज, पत्रिका व अन्य सभी का उद्देश्य जनता को वास्तिविकता और उसके भविष्य की जमीनी सत्यता से दूर रख कर सब अपनी दुकानदारी चलाते हैं। फिर उनके पत्रकारों को कलेक्टर की मजदूरी की दर से कुछ अच्छा ही वेतन दिया जाता है। 70 प्रतीशत को तो लाख रुपये वर्ष की भी वेतन नहीं दी जाती है तो स्वाभिवक है कि वे सभी भी अधिकारियों से दोस्ती कर सच्चाई छुपाकर महाभ्रष्ट निकम्मे अधिकारियों के भी प्रशंसा पत्र छापा करते हैं। सब सरकारी विभागों के अधिकारी इन्हें समय पर लिफाफा नहीं देते हैं। तब ही यह उसके विरूद्ध उसके भ्रष्टाचारों पर कलम चलाते हैं।

अर्थात मीडिया सत्ताधीशों पूंजिपतियों की रखेल की तरह कार्य करता है। स्वाभाविक है कि जनता से करों में वसूली गई अरबों रुपये की धनराशि की कहां कैसे बंदरबाट हुई जनता को मालूम ही नहीं पड़ती। पिछले तीन चार माह से मुख्यमंत्री बेटी बचाओ अभियान से चिपके हुए हैं।

दूसरी तरफ जो जीवित बेटियां है उनकी दाना पानी जो महिला बाल विकास आंगनवाड़ी से लेकर धूर्त और भूखोरी मंत्री तक चट कर रही हैं। स्वाभाविक है रु 1500 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि पूरे म.प्र में यह विभाग खर्च कर रहा है। कागजी आंकड़ो से स्वप्निल संसार रचता है। जिसके परिणाम स्वरूप नवजात से लेकर पांच वर्ष के बच्चे तक कुपोषण का शिकार होकर मौत के मुंह में समा जाते हैं। जबकि

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर एकीकृत बालविकास अधिकारी, जिला अधिकारी, संयुक्त संचालक, संचालक, सचिव, मंत्री तक दोनों हाथों से बटोर कर हजम कर जाते हैं। इंदौर की पूर्व जिला कार्यक्रम अधिकारी के पास घोषित रूप से ससुर व पति के पास करोड़ों की संपत्ति इंदौर के कार्यकाल में ही एकत्रित की गई थी।

स्वामित्वाधिकारी, प्रधान संपादक एवं प्रकाशक अजमेरा एस.पी. कुमार के लिए मीडिया वर्ल्ड कम्यु/ 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर के लिए नवनीत प्रिंटर्स जेल रोड, इंदौर से मुद्रित।
भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9074551045, इंदौर कार्यालयः 0731- 2530859, मो. 9300755803